RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

मासिक, बलौदाबाजार से प्रकाशित

जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं!

वर्ष : 03 अंक : 03 मासिक, बलौदाबाजार,मार्च 2024 E-mail: newsroutine6@gmail.com पृष्ठ : 16 मूल्य : 15 रू.

बस्तर संभाग के सभी जिलों में बनेंगे दंतेश्वरी शक्ति केन्द्र

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर की पावन धरा पर महिला शक्ति के मध्य आना सौभाग्य की बात-मुख्यमंत्री साय

दंतेवाड़ा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा जिले के जावंगा एजुकेशन सिटी के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बस्तर की महिला शक्ति के मध्य आना उनका सौभाग्य है। बस्तर की वीरांगनाएं विपरीत परिस्थितियों में भी समाज और देश की रक्षा के लिए डटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर फाईटर्स, दंतेश्वरी फाइटर्स, सीआरपीएफ सहित सुरक्षा बल पूरी दक्षता के साथ अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बस्तर फाईटर्स और दंतेश्वरी फाइटर्स में तैनात महिला पुलिस जवानों से उनके संघर्षों और वीरता की गाथा सुनकर उनका उत्साह वर्धन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में सेवा देने का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहां के घने जंगल, नदी-नाले, गुफाओं के बीच सुरक्षा बलों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों का कार्य और भी अधिक कठिनाई भरा कार्य है, किन्तु महिलाएं यहां साहस और वीरता के साथ समर्पित होकर कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। महिला शक्ति का यह कार्य अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी शक्तिपीठ में जाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर अपनी महिला शक्ति के लिए प्रसिद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत देश में प्राचीन काल से महिलाओं का सम्मान होता रहा है। वेदों में भी कहा गया है जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। उन्होंने कहा कि शक्ति के लिए दुर्गा की आराधना, समृद्धि के लिए लक्ष्मी की आराधना और ज्ञान के लिए सरस्वती की आराधना की परंपरा इस देश में रही है। अर्थात शक्ति, धन और ज्ञान का भंडार नारी शक्ति के पास है। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान की यह परंपरा आज भी जीवित है तथा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आसीन हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिला शक्ति को सम्मान देने का प्रावधान संविधान में भी किया गया है। लोक सभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे फाइटर प्लेन चला रही हैं, अंतरिक्ष यात्रा कर रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की घोषणा

मूवी आर्टिकल 370 छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री

सपत्नीक आर्टिकल 370 फिल्म देखने मैग्नेटो माल पहुंचे थे मुख्यमंत्री साय

रायपुर। आर्टिकल 370 मूवी छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दी गई है। इस बात की घोषणा मैग्नेटो माल में आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय तथा कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम एवं वन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा विधायकगण भी मौजूद रहे।

इस संबंध में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 बहुत अच्छी मूवी है और इसे सभी को जरुर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने की कल्पना करना बड़ा कठिन था और माना जाता था कि इसे हटाने से घाटी में अशांति फैलेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प और सूझबूझ से कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। इससे वहां न केवल अमन चैन स्थापित हुआ है बल्कि स्वतंत्रता और शांति से जीने का वातावरण भी बन गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में आर्टिकल 370 मूवी को टैक्स फ्री करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विचारधारा एक देश, एक विधान, एक निशान को लेकर है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 इस बुनियादी विचारधारा से असंगत थी। हमारे नेताओं ने आजादी के बाद से ही इसका कड़ा विरोध किया। धारा 370 को हटाने का संकल्प हमने लिया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा हुआ। आज कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। भारत की एकता को लेकर यह बड़ा काम मोदी जी ने किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूवी में कश्मीर के हालात को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और यह बताया गया है कि किस तरह से आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर विकास की राह में पिछड़ रहा था और इसे खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने कितना कठिन संघर्ष किया।

इस मौके पर सांसद श्री सुनील सोनी, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री खुशवंत साहेब, विधायक श्री संपत अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल हरिचंदन ने राजिम कुंभ में की महानदी की महाआरती

रायपुर। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन राजिम कुंभ कल्प 2024 के समापन अवसर पर राज्यपाल श्री हरिचंदन ने त्रिवेणी संगम में साधु संतो के साथ पूरे विधि विधान से महानदी आरती की। इस मौके पर विधायक सर्वश्री रोहित साहू, पुरंदर मिश्रा और जबलपुर से आयी साध्वी प्रज्ञा भारती के साथ ग्यारह पंडितो ने मंत्रोच्चारण के साथ महानदी महाआरती में शामिल हुए।

सनातन धर्म में नदियां और सरोवर हमारे आस्था के केन्द्र रहे हैं। महानदी आरती का उद्देश्य नदियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर उनके प्रति समर्पण, आस्था और संकल्प का भाव सभी के मन में जागृत करना है। महानदी आरती में अनेक ज्योतिपुंज, शंखनाद, कपूर, चवर, आचमन से पूरे मेला परिसर भक्तिमय हो गया। महाआरती में शिव स्त्रोत के बाद सामूहिक महाआरती की गई। श्रद्धालुगणों के आरती और जय-जय श्री राम के जयकारे से पूरा आरती घाट गूंज उठा। महानदी की आरती करने उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी को संरक्षित करने का एक प्रयास है। इसी प्रयास की कड़ी में राजिम कुंभ में वेदरतन सेवा प्रकल्प के संयोजन और संरक्षिका साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य में राजिम कुंभ में भव्य एवं दिव्य महानदी की आरती की प्रतिदिन शुरूआत की गई है।

पाली महोत्सव से मिलती है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अलग पहचान-देवांगन

उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री तथा राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय की उपस्थिति में पाली महोत्सव का हुआ शुभारंभ

कोरबा। महाशिवरात्रि पर्व सहित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित कोरबा जिले के ग्राम केराझरिया में दो दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन,राज्य सभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय सहित अन्य अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि की बधाई दी और कहा कि पाली का ऐतिहासिक शिव मंदिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाली महोत्सव के माध्यम से यहाँ की संस्कृति को अलग पहचान मिल रही है।

महोत्सव में मुख्य अतिथि मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि पाली महोत्सव का आयोजन इस क्षेत्र के लोगों के गौरव से जुड़ा है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के समय हुई थी। इसे भव्य रूप से मनाते हुए राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा कर राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में फैसला लिया है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 31 सौ रुपये धान का मूल्य का वादा पूरा किया जाएगा। शीघ्र ही 12 मार्च को अंतर की राशि किसानों के खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक मूल्य चार हजार से 55 सौ प्रति मानक बोरा किया गया है। महतारी वन्दन योजना के माध्यम से 10 मार्च से सभी पात्र महिलाओं के खाते में राशि हर माह एक हजार रुपए प्रदान की जाएगी।

इस दौरान राज्य सभा सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान महादेव हमारे देश में आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम सबकी कामना है कि महादेव हम सभी देशवासियों को खुश रखे,उन्हें सफलता की राह में आगे बढ़ाए। हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने महिला दिवस से जोड़कर कार्यक्रम का आयोजन करने और महिला कलाकारों का सम्मान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि हमारे देश में नारी शक्ति वंदनीय है। सरकार द्वारा महतारी वन्दन योजना के माध्यम से नारी शक्ति को आर्थिक रुप से सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को लगातार विकास की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने महिला दिवस और महाशिवरात्रि की सभी को बधाई दी। कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने राज्य शासन की योजनाओं के बारे में बताते हुए लोगों को इसका लाभ उठाने तथा पाली महोत्सव के आयोजन में सभी को सम्मिलित होने की अपील की। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने स्वागत भाषण के माध्यम से पाली महोत्सव के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिलाओं को सम्मान देने महिला कलाकारों को मंच दिया गया है ताकि अन्य महिलाएं प्रेरित हो सकें।

इस अवसर पर पूर्व गृहमंत्री श्री ननकीराम कँवर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कँवर, जनपद अध्यक्ष श्री दुलेश्वरी सिदार, अध्यक्ष नगर पंचायत पाली श्री उमेश चंद्रा सहित सरपंच केराझरिया श्री सत्यनारायण पैकरा सहित अन्य अतिथि एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने पाली महोत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुफ्त उठाया।

महतारी वंदन योजना, 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किश्त का अंतरण 10 मार्च को

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महतारी वंदन सम्मेलन से वर्चुअल जुड़कर लोगों को सम्बोधित करेंगे

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 10 मार्च को प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, नगरीय निकाय क्षेत्रों में महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं नगरीय निकायों में आयोजित कार्यक्रमों से सीधे वर्चुअल जुड़कर लोगों को संबोधित करेंगे और हितग्राहियों से बात करेंगे। इस अवसर पर महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से पहली किश्त का अंतरण किया जाएगा। इससे प्रत्येक माह महिलाओं के खाते में 1000 रूपये आएंगे।

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय महिला स्व-सहायता समूहों और विभागीय गतिविधियों पर आधारित स्टॉल का अवलोकन करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 01 मार्च 2024 से नवीन महतारी वंदन योजना लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को एक-एक हजार रूपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस प्रकार महिलाओं को 12 हजार रूपए वार्षिक प्राप्त होगा। योजना के तहत 10 मार्च को पहली बार सहायता राशि दी जाएगी। इससे लगभग 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।

दूरस्थ वन अंचल की माधुरी ने किया जिले का नाम रोशन

- राज्यस्तरीय वर्ड पॉवर चैंपियनशिप में मिला तीसरा स्थान
- कलेक्टर ने दी शाबासी-खूब आगे बढ़ने को दी आशीष

कोरिया। सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती, आभाव भी आड़े नहीं आती बशर्ते ईमानदारी से की गई प्रयास, लगन, मेहनत व प्रोत्साहन जरूरी है। यह बात चरितार्थ की है सोनहत विकासखंड के दूरस्थ ग्राम तर्रा निवासी श्री अनिल कुर्रे व श्रीमती कलावती कुर्रे की कक्षा तीसरी में अध्ययनरत बिटिया माधुरी कुर्रे ने। जानकारी के मुताबिक कुमारी माधुरी कुर्रे के माता-पिता खेतिहर मजदूर हैं। सोनहत विकासखंड के कटगोड़ी संकुल के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला, तर्रा में कक्षा तीसरी में पढ़ाई कर रही कुमारी माधुरी कुर्रे ने राज्यस्तरीय वर्ड पॉवर चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त की है।

बता दें प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के बच्चे अब किसी से कम नहीं है। प्रदेश की विद्यालयीन शिक्षा में रटने की प्रवृत्ति से हटकर सीखने की क्षमता की गति में अद्भुत परिवर्तन आया है। वर्ड पावर चैम्पियनशिप की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के कक्षा दूसरी से कक्षा पांचवीं तक के बच्चों ने प्रतिभागिता की। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह से जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने 7 मार्च को कलेक्ट्रेट कक्ष में कुमारी माधुरी को मुलाकात कराया। कलेक्टर लंगेह ने माधुरी के इस सफलता की प्रशंसा करते हुए खूब शाबासी देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की आशीर्वाद दिए।

बच्चों की प्रतिभा को निखारने की जरूरत

कलेक्टर लंगेह ने कहा कि बच्चों में बहुत प्रतिभा होते हैं, उन्हें निखारने की जरूरत है, उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कलेक्टर लंगेह ने शिक्षक केदारनाथ डिंडोरे को भी इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी।

शिक्षक-शिक्षिकाएं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें

जिले के सभी शिक्षक- शिक्षिकाओं से अपील करते हुए कलेक्टर लंगेह ने कहा कि बच्चों के भविष्य बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इसलिए आप सब ईमानदारी और रुचिपूर्वक बच्चों के मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक, खेलकूद व सांस्कृतिक विकास में योगदान दें, अपने हिस्से का कार्य अवश्य करें।

महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-वर्मा

योजनाओं का लाभ लेकर महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर - लक्ष्मी राजवाड़े

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बुधवार को यहां दशहरा मैदान बलौदाबाजार में आयोजित सशक्त नारी समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 184 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिसमे स्वास्थ्य विभाग से 10, शिक्षा विभाग से 17, महिला एवं बाल विकास विभाग से 21, समाज सेवा क्षेत्र से 7, सशक्त नारी 7, स्वच्छ भारत मिशन से 22 तथा करीब 100 खिलाड़ी शामिल हैं। इसके साथ ही विभिन्न योजना के हितग्राहियों को सामग्री वितरण एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 6 लोगों को 4-4 लाख रुपये के मान से 24 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

मुख्य अतिथि की आसंदी से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। जिसके फलस्वरूप सबका भरोसा हम पर कायम है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है जिसे ध्यान में रख कर लगातार महिलाओं को मजबूत करने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनने के विजन को साकार करने के लिए हम सबको मोदी जी का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव में महतारी सदन बनेगा जिसमें समूह की महिलाएं बैठक या अन्य कार्यक्रम आसानी से कर सकेंगी। पहले चरण में बलौदाबाजार के 40 गांव में महतारी सदन का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जल्द ही जिला खेल के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे कहा कि नारी कैसे आगे बढ़े इसके लिए महिला समूहों का गठन किया गया है। अब महिलाएं केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता के माध्यम से महिलाओं को बैंक से लेनदेन शुरू करने की पहल की है। अब महिलाएं बेहिचक बैंक जा रही हैं। घर-घर शौचालय निर्माण कराकर महिला सम्मान बढ़ाने का काम किये हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कम दाम में गैस सिलेंडर देने की बात को भी हमारी सरकार बहुत जल्द अमलीजामा पहनाएगी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि की पहली किश्त अगले कुछ दिनों में महिलाओं के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। हर माह एक हजार रुपया मिलेगा। जिससे दैनिक खर्च के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्य में लगा पाएंगी। हमारी सरकार बहुत तेजी से घोषणाओं को पूरा कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहने वाली है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक डॉ सनम जांगड़े, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुमन योगेश वर्मा ने भी संबोधित किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री के.एल. चौहान, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नम्रता जैन, जनपद उपाध्यक्ष श्री ईशान वैष्णव, श्री विजय केशरवानी, श्री अशोक जैन, श्री टेसू लाल धुरंधर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं उपस्थित थी।

विकसित भारत रणनीति कक्ष एवं 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म का केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया वर्चुअल शुभारंभ

अम्बिकापुर। केंद्रीय संचार रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने गत दिवस रंग भवन सभागार आकाशवाणी नई दिल्ली में नीति आयोग के (नीति फॉर स्टेट्स) प्लेटफार्म का शुभारंभ किया। नीति आयोग का नीति का स्टेट प्लेटफार्म एक क्रॉस सेक्टरल नॉलेज प्लेटफार्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफार्म शुरुआत से पहले मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' का भी शुभारंभ किया। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफार्म की महत्वपूर्ण विशेषता में 7500 श्रेष्ठ प्रथाओं का जीवंत भंडार और 5000 नीति दस्तावेज, 900 से अधिक डाटा सेट, 1400 उत्तर प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन रणनीति सहित 10 क्षेत्र के ज्ञान उत्पाद शामिल है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से 500 आकांक्षी ब्लॉक के अधिकारीगण जुड़े। कलेक्टर श्री विलास भोस्कर के मार्गदर्शन में जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एनआईसी कक्ष से आकांक्षी ब्लॉक लखनपुर के जनपद सीईओ श्री वेद प्रकाश पाण्डेय व विकासखंड के स्वास्थ्य, शिक्षा, आईसीडीएस, जलसंसाधन, कृषि, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम फेलो उपस्थित रहे।

विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टॉल में लोगों को मिल रहीं न्यायिक जानकारी

राजिम। राजिम कुंभ कल्प में विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें आने वाले लोगों को न्यायिक जानकारियां दी गई कि लोक अदालत के माध्यम से किस प्रकार शीघ्र एवं सस्ता न्याय मिल सकता है। लोक अदालत में समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। तहसील एवं जिला न्यायालयों में प्रत्येक माह निर्धारित तिथि में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। जिसमें देश के सभी न्यायालयों में सभी न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।

रायगढ़ शहर के मैदानों में 3.67 करोड़ की लागत से तैयार होंगी खेल सुविधाएं

रायगढ़। रायगढ़ के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से शहर के विभिन्न खेल मैदानों को संवारने और बेहतर खेल सुविधाएं मुहैय्या कराने के उद्देश्य से 3.67 करोड़ की लागत से खेल अधोसंरचना तैयार होने जा रही है। रायगढ़ शहर में पहली बार युवाओं के रुचि को ध्यान में रखते हुए आधुनिक बॉक्स क्रिकेट कोर्ट बनाए जायेंगे। रायगढ़ शहर के 8 मैदान एवं नगर पंचायत पुसौर के 01 मैदान सहित कुल 9 स्थानों में यह बॉक्स क्रिकेट कोर्ट तैयार किया जाएगा। जिसमें रात में भी खिलाड़ियों के प्रेक्टिस करने के लिए लाईट के साथ सॉफ्टवेयर बेस्ड स्पॉट बुकिंग की सुविधा होगी। इसी तरह 10 जगहों पर बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए जाएंगे। जिसमें प्रमुख रूप से शहर के संजय मैदान रामभांठा, रामलीला मैदान, शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम, पॉलीटेक्निक कॉलेज मैदान, रायगढ़ स्टेडियम बोइरदादार, नटवर स्कूल मैदान जैसे स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही विभिन्न खेल मैदानों में बाउंड्रीवाल भी तैयार किए जायेंगे। इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी। डीएमएफ मद से उक्त कार्य करवाए जायेंगे। वित्त मंत्री श्री

ओ.पी.चौधरी ने गत दिवस रायगढ़ प्रवास के दौरान इन खेल अधोसंरचनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल को निर्देश देते हुए कहा कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। जिससे शहर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को इन सभी सुविधाओं का लाभ जल्द मिल सके।

स्वीकृत कार्यों में संजय मैदान रायगढ़ में 49.80 लाख रुपये की लागत से बाउण्ड्रीवाल फेंसिंग लाईट आदि निर्माण कार्य, संजय मैदान रायगढ़ में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट तथा 20.33 लाख रुपये की लागत से बॉक्स क्रिकेट कोर्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम रायगढ़ में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट तथा 20.33 लाख रुपये की लागत से बॉक्स क्रिकेट कोर्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसी तरह रामलीला मैदान रायगढ़ में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट तथा 20.33 लाख रुपये की लागत से बॉक्स क्रिकेट कोर्ट का निर्माण कार्य, पालीटेक्निक कालेज मैदान में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट तथा 20.33 लाख रुपये की लागत से बॉक्स क्रिकेट कोर्ट का निर्माण कार्य, कोहाकुंडा स्कूल मैदान में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट निर्माण कार्य, छातामुड़ा स्कूल मैदान रायगढ़ में 8.71 लाख रुपये की लागत से बैंडमिंटन कोर्ट बनेगा।

संपादकीय

पॉलिटिकल फंडिंग पारदर्शी हो

इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है और उस पर कोई विशेष टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। पर इस संबंध में जो पहली चीज विचार करने लायक है, वह यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को क्यों लाया गया था? राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गई धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है। उन्हें जो पैसा चंदे या दान के रूप में मिलता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराएंगे। पहले जो धन बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से हासिल होता था, उसकी जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन नगदी चंदे के बारे में पारदर्शिता का पूरा अभाव था। यह तो स्थापित तथ्य है कि हमारे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में काले धन की मौजूदगी जमाने से रही है और इस समस्या के समाधान पर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है। काले धन की वजह से यह चलता रहा कि पैसा देने वाले राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों से बेजा फायदा उठाते रहे। यह स्थिति हमारी राजनीतिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इस पृष्ठभूमि में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाकर यह प्रयास हुआ कि काले धन की समस्या को रोका जाए, उसे हतोत्साहित किया जाए। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू की गई, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है और किसी पार्टी को दिया जा सकता है। एक निर्धारित समयावधि के अंदर पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेती थीं।

इस पद्धति में यह सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं था कि किस पार्टी को किस व्यक्ति या संस्था ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया है। इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन-देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है। जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राजनीतिक दल पैसा जुटाते थे, उसमें भी पारदर्शिता का बड़ा अभाव था। साथ ही, यह भी समस्या थी कि जो लोग भारी मात्रा में नगदी दे रहे हैं, उनके पैसे का स्रोत क्या है, इसका पता लगा पाना असंभव था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा जाए, तो आगे शायद अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी।

महाआख्यान से बनता सत्ता विमर्श

अनंत विजय

दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने देश को सामूहिक हीनभावना से बाहर निकालने का काम किया। नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का आह्वान लाल किले की प्राचीर से किया था। आगे उन्होंने जो कहा उसका अर्थ यह था कि मोदी के शासन काल में देश को उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से लगभग मुक्ति मिली। इसके अलावा भी शाह ने मोदी को कई समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले नेता के तौर पर रेखांकित किया।

जब मुक्ति की बात होती है और उसके साथ कार्यों का लेखा-जोखा दिया जाता है, तो वो कोई साधारण बात नहीं होती है। वह केवल राजनीतिक वक्तव्य नहीं होता बल्कि उस वक्तव्य के पीछे एक सुचिंतित रणनीति होती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों के माध्यम से एक पाठ (टेक्स्ट) का निर्माण करते चलते हैं। उनके भाषणों में देश के उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न भी होता है। पिछले दिनों नरेन्द्र मोदी के भाषणों व क्रियाकलापों को देखें तो वो इसके माध्यम से जो आख्यान रचते हैं, उसमें इन सबकी झलक दिखाई देती है।

मोदी ने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय जो पंच प्रण की घोषणा की थी, वो इसी आख्यान का एक भाग प्रतीत होता है। उसमें भी उन्होंने मुक्ति का स्वप्न देखा था। उसके बाद वो निरंतर विकसित भारत की बात कर रहे हैं। वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न। जब नरेन्द्र मोदी विकसित भारत का आख्यान रचते हैं तो उसके साथ भारतीय अस्मिता को भी जोड़ते चलते हैं। अगर मोदी के इन अस्मितामूलक आख्यान को देखें और उन्हें स्टीफन ग्रीनब्लाट जैसे चिंतक की अवधारणाओं पर कसें, तो स्थिति और स्पष्ट होती है। स्टीफन ग्रीनब्लाट कहते हैं कि हर अस्मिता एक कहानी है। कहानी के बार-बार कहने से ही अस्मिता का निर्माण होता है। हमें यहां ये समझना होगा कि बार-बार कहना क्या है। ये जो बार-बार कहना होता है, यही तो जनता के मानस पटल पर अंकित होकर एक ऐसे पाठ का निर्माण करते हैं, जिससे एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में वातावरण का निर्माण होता है, जिसकी परिणति सत्तामूलक विमर्श में होती है।

हिंदी के आलोचक सुधीश पचौरी ने अपनी पुस्तक 'तीसरी परंपरा की खोज' में लिखा है, कि जिस तरह से इतिहास एक टेक्स्ट (पाठ) है, उसी तरह पद्मावत भी एक टेक्स्ट है और हर सत्ता समूह उसे अपने तरीके से पढ़ सकता है। टेक्स्ट जब मास सर्कुलेशन में होता है, तो उसके मानी की परतें बढ़ती जाती हैं। अगर इस सिद्धांत के आलोक में नरेन्द्र मोदी के रचे आख्यानों को देखें, तो वो जिस टेक्स्ट का सृजन करते हैं, उसके मास सर्कुलेशन में होने के कारण व्याप्ति बढ़ती जाती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने पाठ (टेक्स्ट) का समापन नहीं करते बल्कि एक को दूसरे से जोड़कर एक नया टेक्स्ट जनता के सामने रखते चलते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले वो संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं। संकल्प और सिद्धि की बात करते-करते वे स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय कई प्रकार की मुक्ति का पाठ रचते हैं। इस मुक्ति के बाद वे विकसित भारत के स्वप्न की संरचना करते हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी न केवल नया टेक्स्ट रचते हैं बल्कि उसे इतिहास के तथ्यों के साथ मिलाकर मौखिक इतिहास (ओरल हिस्ट्री) का सृजन भी करते हैं। सुधीश पचौरी कहते हैं कि, मौखिक इतिहास के इतिहासत्व को लेकर अतिरिक्त सजगता की आवश्यकता होती है। मौखिक इतिहास की चुनौतियां भी कई प्रकार की होती हैं। वो वाचक पर निर्भर करती हैं। कई बार मौखिक इतिहास में एक वाचक नहीं होता बल्कि वो अलग-अलग कालखंड में कई वाचकों के माध्यम से आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री के इस मौखिक पाठ का विश्लेषण करते हैं तो इतिहास के साथ-साथ वो एक पावर टेक्स्ट (सत्तात्मक कृति) का निर्माण भी करते हैं। पाठ में जब मुक्ति और स्वप्न का रसायन मिला दिया जाता है, तो वो पावर टेक्स्ट बनता है। आज अगर नरेन्द्र मोदी की साख और विश्वास है, तो उसके पीछे यही पावर टेक्स्ट है।

हमारे देश में पावर टेक्स्ट को समझने का सटीक उदाहरण तुलसीदास कृत श्रीराम चरित मानस है। तुलसीदास ने जब मानस की रचना की तो कथा के साथ मुक्ति का लक्ष्य भी रखा। जब वे मानस रच रहे थे, तब भारत की जनता का मनोबल गिरा हुआ था। हिंदू जनता आक्रांताओं की ज्यादतियों से परेशान थी और वो मुक्ति चाहती थी। तुलसीदास ने इसे समझते हुए एक ऐसे पाठ की रचना की, जिसमें राम जैसा नायक था जिसका चरित्र लोगों में उत्साह का संचार करने वाला था। तीसरी परंपरा की खोज करते-करते लेखक कहते हैं कि रामकथा व उसमें राम का विष्णु के अवतार के रूप में आना और विराट हिंदू कथा में बदलना पूर्व लिखित बहुत-सी रामकथाओं को विस्थापित कर देता है।

भारत में तुलसी की रामकथा की व्याप्ति एक बहुत ही ताकतवर और सघन विमर्श पैदा करती है। इसके मूल में धार्मिक कारणों के अलावा सबसे बड़ा कारण है मानस के प्रतीकों, रूपकों और मुक्ति की कथा के रूप में उसके आदर्शों का सुदीर्घ और सतत संचरण। ये चिह्न एक तरह से हिंदू जनता की स्मृति में चक्कर मारते रहते हैं। भारत में मानस को मनोरंजन का ग्रंथ नहीं बल्कि मुक्ति का ग्रंथ माना जाता है। एक मेटानैरेटिव यह बनता है कि वो कलियुग के अत्याचारों से मुक्ति देने वाली एकमात्र कथा है। तुलसी के मानस के साथ विश्वास और आस्था जुड़कर उसे एक पावर टेक्स्ट बनाती है।

आज नरेन्द्र मोदी जिस तरह पावर टेक्स्ट का आख्यान रच रहे हैं, उससे उनकी नेता वाली छवि के साथ मुक्तिदाता की छवि भी गाढ़ी होती जा रही है।

खून चूस रहे हैं स्मार्ट फोन ...

सुनील कुमार

फ्रांस से एक दिलचस्प खबर आई है कि वहां के एक गांव में स्मार्टफोन के लिए लोगों का बावलापन घटाने के लिए लोगों से रायशुमारी की, और 54 फीसदी लोगों ने स्मार्टफोन पर रोक लगाने की हिमायत की। अब वहां की म्युनिसिपल कमेटी ने तय किया है कि अगर मां-बाप अपने बच्चों को 15 साल की उम्र के पहले स्मार्टफोन न देने पर हामी भरेंगे तो बच्चों को सिर्फ कॉल करने वाला एक साधारण फोन तोहफे में दिया जाएगा। इसी खबर में बताया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ विशेषज्ञों से परामर्श चाहा है कि बच्चों का स्क्रीन टाईम कैसे घटाया जाए। आज बाकी विकसित और संपन्न दुनिया के साथ-साथ फ्रांस में भी स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल लोगों की फिक्र बढ़ा रहा है। समाज में लोगों का आपस में बातचीत करना कम होते जा रहा है, और तमाम लोग अपने-अपने फोन पर जुटे रहते हैं।

यह नौबत सिर्फ विकसित देशों की नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे देश में गरीबों की इतनी आबादी होने के बावजूद सस्ता डेटा पैक एक सबसे बड़ा समाचार रहता है, और अधिकतर लोग अपने इंटरनेट पैकेज के लिए सबसे सस्ता पैक तलाशते रहते हैं। सार्वजनिक जगहों पर हालत यह है कि जिन बाग.बगीचों या तालाब किनारे लोगों को कुदरत का मजा लेने बैठना चाहिए, या आपस में बात करते बैठना चाहिए, वहां पर कमअक्ल स्थानीय संस्थाएं मुफ्त का इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं और लोग कुछ देर के लिए भी चैन से एक-दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते।

भारत में आज हाल यह है कि लोगों ने मानो अपने मोबाइल फोन से शादी ही कर ली है। और सच तो यह है कि शादीशुदा जोड़े भी एक.दूसरे में इस तरह डूबे नहीं रहते, जिस तरह लोग हिन्दुस्तान में दुपहिया चलाते हुए भी सिर और कंधे के बीच मोबाइल दबाकर बात करते दिखते हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग इतना चीख-चीखकर बात करते हैं, कि आसपास के दूसरे लोगों का जीना हराम हो जाता है। घरों के बीच हाल यह है कि हर कोई अपने-अपने फोन या लैपटॉप पर, या अलग-अलग टीवी स्क्रीन के सामने जुटे रहते हैं और एक साथ खाने के मौके भी मोबाइल फोन से दब चुके हैं। चूंकि घर के सभी बड़े लोग अपनी.अपनी स्क्रीन पर जुटे हुए हैं, इसलिए छोटे बच्चे भी किसी तरह का फोन या टीवी जुटाकर उस पर काम करना सीख लेते हैं और यह साबित करने लगते हैं कि टीवी का नाम एक वक्त जिस किसी ने भी इडियट बॉक्स रखा था, सही ही रखा था।

जिन लोगों को इस गंभीर बीमारी की गंभीरता समझ नहीं आ रही है, उन्हें यह बतला देना ठीक होगा कि आज अधिकतर लोग अपने फोन या कम्प्यूटर पर बार-बार सिर्फ यही देखते रहते हैं कि उनसे कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, किसी खबर या संदेश के आए हुए कुछ मिनट गुजर तो नहीं चुके हैं ? मानो कुछ मिनट देर से देखने पर कोई ट्रेन छूटने वाली है। यह बार.बार देखने का सिलसिला कुल मिलाकर यही देखने का साबित होता है कि पिछली बार देखने के बाद से अब तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है। लोग स्मार्टफोन और कम्प्यूटरों पर सोशल मीडिया को पूरे ही वक्त देखते रहने की आदत के शिकार होकर बीमार सरीखे हो गए हैं। अंग्रेजी में इसके लिए 2004 से एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, फोमो, इसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आऊट। इसे मानसिक विशेषज्ञों ने बखान किया है कि लोग आजकल इस तनाव में रहते हैं कि वे सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज छोड़ तो नहीं दे रहे हैं, जो कि दूसरे लोग देख रहे हैं, या वे दूसरों का लिखा या पोस्ट किया कुछ ऐसा तो नहीं अनदेखा कर रहे है, जिसे कि देखना चाहिए। इसके साथ-साथ यह फोमो बर्ताव लोगों को सोशल मीडिया पर लगातार एक-दूसरे से संपर्क करने के लिए भी मजबूर करते रहता है। इसे एक मानसिक बीमारी न सही, एक मानसिक समस्या मान लिया गया है और इससे छुटकारा दिलाने के लिए विशेषज्ञ तरह-तरह के परामर्श का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में 118.24 करोड़ रूपए के 154 कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने नहर विस्तारीकरण सहित विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखी

कवर्धा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कबीरधाम जिले के ग्राम कुरूवा में आयोजित साहू समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर जिले के विकास के लिए 118 करोड़ 24 लाख 16 हजार रूपए की लागत के 154 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री श्री साय से उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप जिले के समग्र विकास के लिए विशेष अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री श्री साय ने लोकार्पण एवं भूमिपूजन से पहले कर्मा मैदान परिसर में विधि-विधान से पूजा की और प्रदेश वासियो को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, सासंद श्री संतोष पांडेय, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, पूर्व संसदीय सचिव डॉ सिया राम साहू, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला रामकुमार भट्ट सहित समाज प्रमुख उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में मछली पालन और उद्यान विभाग की हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत 1 करोड़ 50 लाख 30 हजार रूपए की सामाग्री का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कबीरधाम जिले में सिंचाई क्षमता एवं जलाशय की नहर विस्तारीकरण के लिए 107 करोड़ 07 लाख 94 हजार रूपए की लागत से कुल 09 कार्या का शिलान्यास एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने 84 करोड़ 70 लाख 72 हजार रूपए की लागत से विकासखंड सहसपुर लोहारा की बोरोदाखुर्द जलाशय योजना का निर्माण कार्य, 13 करोड़ 94 हजार रूपए की लागत से विकासखंड कवर्धा की सरोदा मध्यम जलाशय अंतर्गत अगरी माईनर का रिमाडलिंग एवं विस्तारीकरण कार्य, 6 करोड़ 10 लाख 69 हजार रूपए की लागत से भाटकुंडेरा (ठाठापुर) व्यपवर्तन योजना का निर्माण कार्य, 1 करोड़ 59 लाख 60 हजार रूपए की लागत से विकासखंड सहसपुर लोहारा की सोनझरी जलाशय योजना के आरबीसी एवं एलबीसी के नहर लायनिंग कार्य, 2 करोड़ 43 लाख 49 हजार रूपए की लागत से विकासखंड बोड़ला की सरईपतेरा व्यपवर्तन योजना के गेट सुधार एवं नहर लाईनिंग कार्य, 2 करोड़ 97 लाख 27 हजार रूपए की लागत से छीरपानी मध्यम जलाशय अंतर्गत छीरपानी एवं निरीक्षण कुटीर का जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य, 2 करोड़ 10 लाख 49 हजार रूपए की लागत से सुखानाला व्यपवर्तन का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य, 2 करोड़ 92 लाख 43 हजार हजार रूपए की लागत से राजपुर व्यपवर्तन कार्य प्रारंभ से 5000 मीटर तक कार्य, 2 करोड़ 92 लाख 31 हजार रूपए की लागत से बेल्हरी जलाशय के शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहर का मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य लंबाई 6200 मीटर के कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंडी मद अंतर्गत 11 करोड़ 03 लाख 22 हजार रूपए की लागत से 143 विकास कार्य और निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने 6.50-6.50 लाख रूपए की लागत से ग्राम पंचायत कल्याणपुर में दो सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 आईएएल अफसरों का तबादला

रायपुर। राज्य सरकार ने 7 आईएएस के विभागों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे मुकेश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनके पदभार ग्रहण से डॉ. कमलप्रीत सिंह सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के प्रभार से मुक्त होंगे।

वहीं आईएएस हिमशिखर गुप्ता भी वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) से मुक्त होंगे। उनका शेष प्रभार यथावत रहेगा। अंकित आनंद से वित्त सचिव का प्रभार लेकर वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग का सचिव बनाया गया। उनके पास सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और सचिव बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। आईएएस मोहम्मद कैसर अब्दुलहक से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग वापस लिया गया है। वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव रहेंगे।

एमबीबीएस करने में दो छात्रों ने लगा दिए 15 साल

रायपुर। एमबीबीएस कोर्स साढ़े चार साल का है, लेकिन नेहरू मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत दो छात्र बमुश्किल 14 व 15 साल में पास हो सके। पास होने के बाद दोनों छात्रों की इंटर्नशिप पोस्टिंग लगा दी गई है।

एमबीबीएस कोर्स साढ़े चार साल का है, लेकिन नेहरू मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत दो छात्र बमुश्किल 14 व 15 साल में पास हो सके। पास होने के बाद दोनों छात्रों की इंटर्नशिप पोस्टिंग लगा दी गई है। पिछले साल ही 2009 बैच का पीएमटी टॉपर ने एमबीबीएस उत्तीर्ण की थी। अभी वह भी इंटर्नशिप कर रहा है। एक साल इंटर्नशिप करने के बाद पास छात्र दो साल के बांड पर ग्रामीण सेवा में जाएंगे। इसके बाद ही वे प्रेक्टिस कर पाएंगे।

प्रदेश में ऐसे बहुत कम छात्र हैं, जो 14 या 15 साल में एमबीबीएस पास करते हों। एक अनुमान के अनुसार पिछले 5 साल से औसतन 80 से 85 फीसदी छात्र साढ़े पांच या छह साल में एमबीबीएस पास कर लेते हैं। 2009 बैच के विनोद कुमार सिदार (बदला हुआ नाम) व 2010 बैच में परब सिंह (बदला हुआ नाम) ने एडमिशन लिया था। पहली ही परीक्षा में दोनों छात्र दो से तीन विषय में फेल हो गए।

इसके बाद वे 2023 तक एक-एक विषय में फेल होते रहे और रिफर्ड बैच के साथ परीक्षा देते रहे। जनवरी में आयोजित परीक्षा में दोनों छात्र पूरी तन्मयता व लगन से शामिल हुए। सप्ताहभर निकले रिजल्ट में दोनों पास घोषित किए गए। विनोद को 2450 में 1326 व परब को 1333 नंबर मिले हैं। पिछले साल पीएमटी टॉपर छात्र पास हुआ। दरअसल 2009 में मुन्ना भाई के सहारे वह पास हुआ था। सीआईडी जांच भी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद टॉपर समेत दूसरे छात्रों ने एमबीबीएस की पढ़ाई जारी रखी और वे पास होते गए।

अब चार अटेंप्ट में पास नहीं करने वाले सीधे कॉलेज से बाहर

अब नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने नियम बदल दिया है। चार अटेंप्ट में एमबीबीएस पास करने वाले छात्र सीधे कॉलेज से बाहर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे तीन छात्र बाहर हो चुके हैं। जबकि एक छात्र को जीवनदान मिला है।

रजिस्ट्रेशन आफ न्यूज पेपर्स (सेन्ट्रल रूल्स 1965 के अन्तर्गत) 'न्यूज रुटीन' मासिक पत्रिका के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक जानकारी

घोषणा, फार्म-4 (नियम-8 देखिए)

1. प्रकाशन स्थल	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
2. प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या मुद्रक भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं तो मूल देश	-	भारतीय
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
4. मुद्रक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या प्रकाशक भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं तो मूल देश	-	भारतीय
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा,(छग) 493338
5. सम्पादक का नाम	-	गुलाब दास दीवान
क्या प्रकाशक भारतीय नागरिक हैं या विदेशी हैं तो मूल देश	-	भारतीय
पता	-	ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, (छग) 493338
6. उन व्यक्ति के नाम व पते जो समाचारपत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक सम्पूर्ण स्वामित्व के हिस्सेदार हों	-	गुलाब दास दीवान ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, (छग) 493338

मैं गुलाबदास दीवान एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि शीर्षक न्यूज रुटीन जो बलौदाबाजार से प्रकाशित तथा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान रायपुर से मुद्रित होने वाले समाचार पत्र का मुद्रक एवं प्रकाशक हूं तथा उक्त समाचार पत्र के संदर्भ में यहां दिये गये निम्न विवरण मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य हैं।

दिनांक 1-3-2024

गुलाब दास दीवान
पदनाम- मुद्रक / प्रकाशक / स्वामी

मरीजों की बढ़ी मुसीबत, हड़ताल पर गईं मितानिनें

बलौदाबाजार। प्रदेशभर की मितानिनें गुरुवार से 5 दिन की हड़ताल पर चली गई हैं। ग्रामीण इलाकों में गर्भवतियों, नवजातों की देखभाल से लेकर कुष्ठ, टीबी जैसे रोग और दस्त पखवाड़ा जैसे बड़े अभियानों की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। जाहिर है कि इनके हड़ताल पर रहते तक ये सारी अहम जिम्मेदारियां भगवान भरोसे पूरी होंगी।

प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर जिले की मितानिनें 7 से 10 मार्च तक अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर जिले में प्रदर्शन करेंगी। 11 तारीख को राजधानी में हड़ताल होगी। चूंकि ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का संचालन मितानिनों के जरिए होता है। लिहाजा, मितानिनों की हड़ताल से निश्चित तौर पर सारी योजनाएं तथा व्यवस्थाएं ठप रहने वाली हैं। हड़ताल के पहले ही दिन धरनास्थल दशहरा मैदान में सैकड़ो की संख्या में मितानिनों ने अपनी दो सूत्री मांगो को पूरा करने के लिए जमकर नारेबाजी की। संघ की प्रदेश अध्यक्ष सरोज सेंगर, जिलाध्यक्ष सती वर्मा ने बताया, भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया था। संघ इसे पूरा करने की मांग कर रहा है।

राजनांदगांव लोस सीट पर भाजपा-कांग्रेस में कांटे की टक्कर

राजनांदगांव। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें दो वर्तमान सांसदों को मौका दिया गया है। चार सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं पांच सांसद विधानसभा चुनाव लड़कर जीते हैं। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। 11 लोकसभा क्षेत्रों में 9 नए चेहरे पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषित किए हैं जिन्हें अब मोदी के 400 पार वाले आंकड़े तक पहुंचने में मदद करनी होगी। जीत कर दिल्ली जाना होगा।

जिन दो वर्तमान सांसदों को पार्टी ने मौका दिया है उसमें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद संतोष पांडेय का नाम भी शामिल है, जिसे लगातार दूसरी बार पार्टी ने मौका दिया है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने 25 साल बाद किसी जीते हुए प्रत्याशी को दूसरा मौका दिया है। इससे पहले तक केवल एक बार जीते या हारे हो, चेहरा बदल जाता रहा है, लेकिन इस बार पार्टी ने अपने पुराने फैसलों को बदलते हुए निर्णय लेकर मतदाताओं को व कार्यकर्ताओं को चौकाया है। भाजपा अपना प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस से एक कदम आगे निकल चुकी है। इससे प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार के लिए अधिक समय मिल चुका है।

साल 2019 के प्रचंड मोदी लहर में मौजूदा सांसद संतोष पांडेय 1 लाख 11 हजार 966 मतों से जीते थे, जबकि

कांग्रेस के भोलाराम साहू को सबसे कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था, बावजूद इसके कम वोटों से जीतने का असर दिखा था। इस चुनाव में पार्टी ने फिर से संतोष पांडेय को मौका दिया है, जो पिछले चुनाव की तुलना में उनके लिए आसान नहीं होगा। कार्यकर्ताओं में दबी जुबान में विरोध होने लगा है। हालांकि इसे शुरूवाती दौर का विरोध माना जा रहा है। बाद में सभी को मना लिया जाएगा।

2000 के बाद से भाजपा का कब्जा

राजनांदगांव लोकसभा सीट पर वर्ष 1952 से लेकर 2014 तक 16 बार चुनाव हुए। इनमें से ज्यादातर नतीजे कांग्रेस के ही पक्ष में रहे। वहीं वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से यहां 2007 में एक उपचुनाव के अलावा तीन लोकसभा चुनाव हुए हैं। 2007 के उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1999 के बाद से सभी चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019 में राजनांदगांव लोकसभा सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा।

आठ विधानसभा की हिस्सेदारी

राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव और कबीरधाम दोनों जिले आते हैं। राजनांदगांव में छह और कबीरधाम में दो विधानसभा सीटें हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाली विधानसभा की आठ सीटों में कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, मानपुर-मोहला शामिल हैं।

विधानसभा में हार जीत का दौर चलता रहा

राजनांदगांव लोकसभा सीट इसलिए हाईप्रोफाइल है क्योंकि यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सांसद रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा को हार मिली, लेकिन वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी मिली।

घर-घर कचरा उठाने वाली 5 युवतियां बदल रहीं अपनी जिंदगी, पूरी की एमए-बीए की पढ़ाई

अंबिकापुर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। अगर मजबूत इच्छाशक्ति हो तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ अंबिकापुर के ठनगनपारा एसएलआरएम सेंटर में काम करने वाली 5 युवतियां ने कर दिखाया है। ये युवतियां जहां एसएलआरएम सेंटर में काम करते हुए परिवार को संभाल रहीं हैं वहीं इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी है। इनमें से 2 युवतियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अब वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई हैं।

8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। देश की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो।

आज हम हम आज बात करने जा रहे हैं मंजूषा कुजूर, रामेश्वरी तिर्की, सीता तिर्की, सरस्वती व सुगंती की। ये पांचों युवतियां अंबिकापुर के ठनगनपारा एसएलआरएम सेंटर में काम करतीं हैं। इनका काम रिक्शा से घर-घर जाकर कचरा कलेक्शन करना, कचरे की छंटाई करने के साथ-साथ कचरा शुल्क वसूलना है।

ये काम के बाद बचे समय में अपनी पढ़ाई करतीं हैं। एसएलआरएम सेंटर में काम करते हुए मंजूषा कुजूर व रामेश्वरी तिर्की ने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तथा सीता तिर्की, सरस्वती व सुगंती ने ग्रेजुएट कर लिया है। अब पांचों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरु कर दी है।

'पढ़ाई ही एक मात्र रास्ता जो बदलेगी हमारी जिन्दगी'

मंजूषा कुजूर व रामेश्वरी एसएलआरएम सेंटर में काम करते हुए एमए तक की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं। मंजूषा बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम सुवारपारा जबकि रामेश्वरी राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डकवा की रहने वाली हैं। ये दोनों अपनी संघर्ष की कहानी बताते हुए कहतीं हैं कि इनके माता-पिता खेती किसानी करते हैं।

माता-पिता ने 10वीं-12वीं तक किसी तरह पढ़ाया, लेकिन आगे की पढ़ाई कराने की स्थिति में नहीं थ, जबकि हमलोग आगे भी पढना चाहते थे। पढ़ाई पूरा करने के उद्देश्य से मंजूषा ने वर्ष 2019 में अंबिकापुर आकर एसएलआरएम सेंटर में काम शुरु किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी।

वहीं रामेश्वरी वर्ष 2016 से एसएलआरएम सेंटर में रहकर काम कर रही है और पढ़ाई जारी रखी थी। ये दोनों युवतियां काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूर्ण कर चुकी हैं। इन दोनों से पढ़ाई के महत्व के बारे में पूछने पर बताया कि पढ़ाई ही एक मात्र रास्ता है जो हमारी जिन्दगी बदलेगी।

रायगढ़ में नहीं थम रहा हादसा!

रायगढ़। रायगढ़-घरघोड़ा मार्ग हादसों का डगर साबित हो रहा है। एक तो इस मार्ग की हालत खराब है ऊपर से भारी वाहन की सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से किए जाने वाली वाहनों की पार्किंग हादसे का कारण बन रहा है। पिछले तीन दिन की स्थिति पर ही गौर करें तो तीन हादसे में छह लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस सड़क में निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन इसकी गति कछुआ चाल से ज्यादा नहीं है।

रायगढ़-घरघोड़ा की हालत विगत कई सालों से बदतर स्थित में है। हालांकि इसमें सुधार का कार्य किया जारहा लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। मजबूरीवश लोग मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं। इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को धुल के गुब्बार और जाम की स्थिति से हमेशा जुझना पड़ रहा है।

पिछले छह दिनों में इस मार्ग पर तीन लोगों की भारी वाहन की चपेट में आकर असमय मौत हो चुकी है। इन हादसों के होने के पीछे एक कारण यह भी सामने आ रही है कि गेरवानी से लेकर बरौद तक सड़क के दोनों साइड में भारी वाहन के चालक सड़क को ही पार्किंग बनाकर वाहन खड़ी कर रहे रहे हैं। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले यात्री बसों के अलावा निजी वाहनों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है। इतना ही नहीं कई बार ऐसी भी स्थिति निर्मित हो जाती है कि दो भारी वाहन के चालकों के द्वारा आपस में विवाद होने के बाद उनके द्वारा बीच सड़क में गाड़ी खड़ी कर आम लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन वाहन चालकों पर न तो यातायात विभाग द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है और न ही स्थानीय पुलिस द्वारा कोई पहल हो रहा है, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी इस मार्ग पर हादसा रोकने के कोई उपाय नहीं किए जा रहे।

डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन बनेगा अमृत भारत स्टेशन

12 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, यात्रियों को मिलेगी सुविधाएं

डोंगरगढ़। मां बमलेश्वरी माता के दरबार में पहुंचने के नजदीक डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब बदलने वाली है। इस स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे 12 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस रेलवे स्टेशन को रेलवे अमृत भारत स्टेशन बनाने जा रहा है, जिसमें यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा।

रेल अफसरों के अनुसार आने वाले 40-50 सालों के बढ़ते यातायात को देखते हुए ऐसा प्लान किया गया है। क्योंकि बिलासपुर रेलवे जोन के तीनों रेल मंडलों रायपुर, बिलासपुर और नागपुर के अंतर्गत कई छो-छोटे स्टेशनों को रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना अमृत भारत स्टेशन बनाने में शामिल किया गया है।

उसी के तहत डोंगरगढ़ स्टेशन में काम होने जा रहा है। इस योजना में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 49 स्टेशनों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के 32 स्टेशनों का पुनर्विकास का प्लान है। अभी हाल ही में 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के द्वितीय चरण में होने वाले कामों का भूमिपूजन ऑनलाइन दिल्ली से किया था।

ऐसी सुविधाएं होंगी स्टेशन में

डोंगरगढ़ स्टेशन में आने और जाने के लिए अलग मार्ग, चौड़ा फुट ओवरब्रिज, वाल पेंटिंग्स व म्यूरल्स में स्थानीय संस्कृति की झलक, आकर्षक कॉनकोर्स, वेटिंग हॉल में फर्नीचर्स, कोच एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, आकर्षक पोर्च, पार्किंग्स की सुविधा, चौड़ा फुटपाथ, स्टेनलेस स्टील चेयर, अपग्रेडेड अनारक्षित टिकट और पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइनेज, स्टेशन परिसर में हाई मास्ट से प्रचूर लाइट , सीसीटीवी, बुजुर्ग, बच्चे एवं दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट एवं 2 एस्केलेटर, गार्डन व मनमोहक लैंड स्केपिंग, आधुनिकता व परंपरा को एक साथ प्रदर्शित करते फसाड जैसी सुविधाएं विकसित होंगी।

साय कैबिनेट का अनुकम्पा नियुक्ति पर बड़ा फैसला

जिले में पद खाली नहीं तो संभाग में मिलेगी नौकरी,

रायपुर। विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक के दूसरे दिन ही अनुकंपा नियुक्ति की राह आसान हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। अब विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र रिक्त नहीं है, तो कलेक्टर को आवेदन भेजा जाएगा।

यदि जिलों में पद रिक्त नहीं है, तो नियुक्ति के लिए संभागायुक्त को पत्र भेजा जाएगा। इसके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए समस्त विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, समस्त विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी नियुक्ति

प्रदेश के सभी कलेक्टरों का कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर भेजेंगे। पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है

70 बच्चों को गोद लेकर नि:शुल्क में सिखा रहीं शास्त्रीय संगीत ताकि हुनरमंद बन सकें बच्चे

राजनांदगांव। एक महिला चाहे तो पूरे समाज और देश को बदलकर रख सकती है। इसलिए हमारे देश में नारी शक्ति का हमेशा सम्मान होता रहा है। महिलाएं भी जज्बे के साथ समाज और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहीं हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक हैं शिक्षिका पारुल चतुर्वेदी। पारुल वर्तमान में टेड़ेसरा स्थित मिडिल स्कूल में एलबी शिक्षिका हैं। शिक्षा में नवाचार के क्षेत्र में कई बार सम्मानित हो चुकीं उक्त शिक्षिका ने गांव के बच्चों का भविष्य संवारने की ठानी है।

टेड़ेसरा सहित आसपास के 70 स्कूली बच्चों को गोद लेकर निशुल्क में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, सुगम संगीत की शिक्षा दे रहीं हैं ताकि बच्चे आगे चलकर हुनरमंद बन सकें और आसानी से किसी भी संस्थान में नौकरी कर सकें। पारुल इन बच्चों को केवल निशुल्क में शिक्षा ही नहीं दे रहीं हैं बल्कि शास्त्रीय संगीत से जुड़ी परीक्षा में भी आर्थिक रूप से मदद करती हैं।

बच्चे परीक्षा देकर शास्त्रीय संगीत में पारंगत होने लगे हैं। शिक्षिका पारुल ने बताया कि इंग्लिश टीचर के रूप में शिक्षा विभाग में 2005 में पोस्टिंग हुई। इसके बाद से कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के अंग्रेजी विषय में दिए गए पोयम को छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में कनवर्ट कर बच्चों को पढ़ना सिखाती हैं।

इसलिए संगीत की सीख दे रहीं

पारुल का कहना है कि गांव के बच्चे पढ़ाई तो करते हैं पर सरकारी जॉब सहित अन्य संस्थानों में जानकारी के अभाव में नौकरी नहीं कर पाते। गांव तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए ठाना है कि गांव के बच्चों को हुनरमंद बनाना है। इस वजह से स्कूल में हर शनिवार को शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, नृत्य और चित्रकला की बारीकियां सिखाने दो घंटे की क्लास लेती हैं। यह सिलसिला तीन साल से चल रहा है। पहले 30 से 40 बच्चे आते थे पर अब टेड़ेसरा सहित मगरलोटा, देवादा, इंदावानी गांव के लगभग 70 बच्चे प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं।

परीक्षा का खर्च स्वयं उठाती हैं

पारुल ने बताया कि शास्त्रीय संगीत का कोर्स छह साल का है। प्रशिक्षण के साथ डिग्री के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। गोद लिए गए बच्चों को प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ के माध्यम से परीक्षा दिला रहीं हैं। परीक्षा में आने वाले खर्च का वहन स्वयं करती हैं। चित्रकला की भी परीक्षा दिलाई जाती है। बच्चे रुचि लेकर पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।

चुनावी साल में 482 करोड़ का बजट

पिछले साल से 100 करोड़ रु. ज्यादा, फिर भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं

भिलाई। नगर निगम के मौजूदा परिषद की अंतिम बजट बैठक बेहद हंगामेदार रहा। अगली बजट बैठक से पहले फिर से प्रतिनिधित्व के इच्छुक सदस्यों को चुनावी रण में जाना होगा। लिहाजा शहर सरकार के बजट में शामिल प्रस्तावों से लेकर सदस्यों के मुद्दों तक में इसका असर देखने को मिला। चुनावी साल के मद्देनजर शहर सरकार ने जहां पिछले साल से करीब 100 करोड़ ज्यादा यानी 482 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पेश किया, वहीं विपक्ष ने भी जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाकर चुनाव के लिहाज से जनता को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। यहां तक कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने भी शहर सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा।

खास बात यह रही कि भारी भरकम बजट के बाद भी इस बार कोई भी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया। वहीं पूरे दिन गहमागहमी के बीच चर्चा के बाद देर शाम बजट बहुमत से पारित कर लिया गया। निगम कार्यालय स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित बैठक में महापौर ने 482 करोड़ 50 लाख 34 हजार का बजट रखा। उन्होंने बताया कि नगर निगम के संपूर्ण स्रोतों और राज्य व केंद्र सरकार से संभावित अनुदान के आधार पर इस आय का अनुमान किया गया है। वहीं इस बार 432 करोड़ 39 लाख 79 हजार रुपए खर्च का अनुमान है। इस तरह वित्तीय वर्ष में नगर निगम को करीब 10 लाख 55 हजार रुपए आय का अनुमान है। उन्होंने बताया कि जनहित को ध्यान में रखकर विभिन्न मदों में राशि का प्रावधान किया गया है।

बैठक में सत्तापक्ष को उस समय बेहद किरकिरी का सामना करना पड़ा जब शहर सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग की मंत्री जयश्री जोशी ने महापौर और कमिश्नर लोकेश चंद्राकर पर सवाल खड़ा कर दिया। जयश्री का कहना था कि राज्य शासन की ओर से 43 अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति मिली है, लेकिन महापौर और कमिश्नर इस पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। उनका आरोप था कि सामान्य प्रशासन विभाग के सामानांतर अलग से विभाग चलाकर नियुक्तियां की जा रही है। ऐसे में एमआईसी को भंग कर दिया जाना चाहिए। सत्तापक्ष को इस पर ठोस जवाब देते नहीं बना।

एक घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 14 सवाल

सामान्य सभा की बैठक के तहत इस बार प्रश्नकाल भी ऐतिहासिक रहा। सामान्यत: एक घंटे तक चलने वाले प्रश्नकाल में 5 से 6 सवाल और उनके जवाब हो पाते थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 14 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए। इन सवालों का संबंधित विभाग के प्रभारियों ने जवाब भी दिया। हालांकि इससे अधिकतर सवालों के जवाब पर प्रतिप्रश्न करने का अवसर अधिकतर सदस्यों को नहीं मिल पाया। इसे लेकर नाराजगी भी सामने आई।

विकास शुल्क बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मचा घमासान

निगम प्रशासन की ओर से बजट के साथ विकास शुल्क में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव लाया गया। शहर सरकार की ओर से महापौर ने इस पर मिलजुलकर फैसले की अपील की। लंबे समय से विकास शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। विकसित व अविकसित क्षेत्र के हिसाब से शुल्क बढ़ाने से निगम को 10 से 15 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। इससे निगम को कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य मदों में भुगतान में सहुलियत

कांग्रेस विधायक ध्रुव को नहीं मिला सरकारी आवास तो चले गए जंगल

नक्सल इलाके में घूमते रहे,

गरियाबंद। बिंद्रानवागढ़ विधानसभा प्रदेश के घनघोर नक्सल इलाकों में एक है। कांग्रेस के जनकराम ध्रुव यहां से विधायक हैं। सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने उन्हें 2 पीएसओ और पायलेटिंग में 1+3 (4) पुलिसवाले दिए हैं। लेकिन, सरकारी आवास नहीं दिया। माननीय जब खुद ही बेघर हैं तो रक्षकों को कहां रखें! लगातार तीन महीने तक प्रशासन से आवास की गुहार लगाते थक गए। किसी ने न सुनी तो विधायक ने बुधवार को सिक्यूरिटी ही छोड़ दी। पूरे दिन बिना सुरक्षा नक्सल प्रभावित इलाकों में घूमते रहे। उनके इस एक एक्शन ने सिस्टम की कलई खोल दी है।

बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में कुल 685 गांव आते हैं। इनमें से 70-75 फीसदी गांव नक्सल प्रभावित हैं। मौजूदा विधायक जनक ध्रुव का पैतृक निवास मैनपुर से लगे नहारबिरी गांव में है। वे रोज यहां से 80 किमी दूर देवभोग जाते हैं क्योंकि उनके विधानसभा से जुड़े कामों के लिए उपयुक्त जगह है। दरअसल, तकरीबन 200 किमी क्षेत्र में फैले बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के लोगों के लिए देवभोग सेंट्रल प्वॉइंट है। जनक तीन महीने में 4 से 5 बार आवास के लिए आवेदन-निवेदन कर चुके हैं।

बुधवार दोपहर गरियाबंद के अपर कलेक्टर का एक बयान बयान आया। विधायक को सरकारी आवास न देने का कारण ये बताया कि उन्हें पहले ही रायपुर में आवास आवंटित है। हालांकि, पत्रिका ने जब विधायक से बात की तो उनका कहना था, रायपुर का घर सरकारी नहीं है। खुद का है। बता दें कि देवभोग में विधायक के लिए 10 साल पहले आवास दिया गया था। वो नेता अब विधायक नहीं रहे। आवास अब भी उन्हीं के पास है।

जिला मुख्यालय गरियाबंद के अफसरों को जब पता चला कि विधायक सुरक्षा छोड़कर अकेले ही अति संवेदनशील इलाकों में घूम रहे हैं तो उनके हाथ-पांव फूल गए। दोपहर करीब 3 बजे देवभोग के एसडीएम हितेश पिस्दा ने विधायक ने फोन पर संपर्क किया। यहां से मारन-मनौव्वल का दौर शुरू हुआ जो करीब आधे-पौन घंटे तक चलता रहा। विधायक इस आश्वासन पर माने कि गुरुवार को देवभोग में उन्हें आवास मुहैया करा दिया जाएगा। शाम 5 बजे विधायक वापस मैनपुर स्थित अपने पैतृक निवास में पहुंचे। तब कहीं जाकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस बहाल हो पाई।

मैनपुर से लगे गांव में स्थित अपने पैतृक निवास में सुबह 10 बजे सुरक्षा छोड़ने के बाद सबसे पहले जुगाड़ गए। फिर इंदागांव से भैंसमुड़ी, अमलीपदर, उरमाल, ओडिशा होते हुए वापस बिंद्रानवागढ़ विधानसभा के बरही गांव पहुंचे। बता दें कि इनमें से जुगाड़ और इंदागांव अति संवेदनशील इलाके हैं। इसके अलावा मैनपुर से धुरवागड़ी तक 60 किलोमीटर घना जंगल पड़ता है। इसे भी एक्टिव नक्सलियोंका इलाका माना जाता है। इतने अतिसंवेदनशील इलाकों में विधायक के अकेले घूमने की खबर पाकर अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि, कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन, सुरक्षा न होने से कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी।

विधायक ने लौटाई सुरक्षा

कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव का कहना है कि उन्हें तीन माह बाद भी आवास आवंटित नहीं हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उनको सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराई थी, जिसे उन्होंने यह कह कर लौटा दी कि मैं सुरक्षाकर्मियों को कहां रखूंगा, मेरे रहने के लिए ही घर नहीं है।

दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने में अहम भूमिका निभा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-चौधरी

रायगढ़। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत आज रायगढ़ जिले में 291 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी जिला मुख्यालय के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाटी स्टेडियम में आयोजित 84 जोड़ो के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए एवं नवदपत्तियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किए।

सामूहिक विवाह में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने नव विवाहित जोड़ों को पुष्प वर्षा कर वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए रायगढ़ में विवाहित सभी 84 जोड़ों को अपनी ओर से 5-5 हजार रुपये की स्वेच्छा अनुदान राशि देने की भी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शादी कराने के साथ ही दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत प्रदेश में लगातार सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आज विवाह में शामिल सभी नवदंपत्तियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने सामूहिक विवाह में आगे आकर समाज को एक अनुकरणीय संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज विवाह बंधन में बंधे सभी बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ लेने का आग्रह किया, जिससे उन्हें सालाना 12 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आज विवाह में शामिल सभी नवजोड़ों को राज्य शासन की ओर से 21-21 हजार रूपये की सहायता राशि दी जा रही है। इस मौके पर उन्होंने नवदपत्तियों को सहायता राशि का चेक भी वितरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार पटेल, श्री राधेश्याम राठिया, श्री विजय अग्रवाल, श्री उमेश अग्रवाल, श्रीमती पूनम दिबेश सोलंकी, श्री सुभाष पाण्डेय, श्री कौशलेष मिश्रा, श्री श्रीकांत सोमावार, श्री रत्थू गुप्ता, श्री सुरेश गोयल, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव, नगर पुलिस अधीक्षक श्री आकाश शुक्ला, डीपीओ श्री एल.आर.कच्छप उपस्थित रहे।

तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य शासन ने नियुक्त किया कार्यवाहक अध्यक्ष

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद श्रीमती अमरीका कृष्ण कुमार साहू को तखतपुर नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद श्री धनलाल देशलहरे को मारो नगर पंचायत का और मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद श्री परमानंद साहू को सरगांव नगर पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।

फर्जी धान खरीदी के मामले में समिति प्रबन्धक एवं प्रभारी पर एफआईआर दर्ज

सरगुजा। सरगुजा जिला प्रशासन की टीम द्वारा विकासखंड लखनपुर के धान खरीदी केंद्र अमलभिट्ठी में धान खरीदी हेर-फेर के मामले में कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने मामले की पुष्टि पर समिति प्रबंधक एवं प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उल्लेखनीय है कि उक्त धान खरीदी केंद्र में गत 19 जनवरी को 1957.60 क्विंटल फर्जी धान खरीदी कर कुल 42 लाख 73 हजार 440 रुपये की शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसमें जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी द्वारा समिति प्रबन्धक जैनेन्द्र प्रसाद राजवाड़े एवं धान खरीदी प्रभारी सह डाटा एंट्री ऑपरेटर शैलेन्द्र राजवाड़े से पूछताछ की गई थी। अब मामले की पुष्टि होने पर इनके विरुद्ध थाना दरिमा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

आबकारी विभाग ने शराब माफियाओं पर कसा नकेल

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार तथा सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में 05 मार्च 2024 को प्रात: गश्त के दौरान आबकारी विभाग द्वारा वृत-धमधा अन्तर्गत ग्राम बानबरद थाना नंदिनी नगर में अवैध शराब के विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपिया सतरूपा आडिल, निवासी - ग्राम बानबरद थाना नंदिनी नगर के कब्जे से कुल 31 पाव देशी मदिरा मसाला, जिसकी कुल मात्रा 5.580 बल्क लीटर जप्त किया गया। उक्त मदिरा का कुल बाजार मूल्य 3410 रू है। प्रकरण में आरोपिया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू के द्वारा विवेचना में लिया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा जिले में आबकारी टीम गठित कर अवैध शराब के व्यापार, विक्रय, परिवहन तथा धारण करने वाले आदतन तथा गैर आदतन अपराधियों की पतासाजी तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, अपराधिक पारम्परिक मार्गों, होटल, ढाबों में लगातार गश्त की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण मे परी. आबकारी उपनिरीक्षक श्रीमति गीतांजलि तारम, श्रीमति अनामिका टोप्पो, प्रियंक ठाकुर, आबकारी आरक्षक त्रिलोक नाथ इन्दोरिया, वाहन चालक दुर्गा साहू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग

दुर्ग। सचिव छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित है। जिसके अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित संतानो को उनके शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे-पीएससी, सीजी व्यापम, एसएससी, बैंकिंग, रेल्वे, पुलिस भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत समय-समय पर जारी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधी के लिये नि:शुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा। आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें एवं कार्यालय से भी संपर्क कर सकते है।

उड़नदस्ता दल तथा स्थैतिक निगरानी दल की बैठक सह प्रशिक्षण

मनेन्द्रगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल सिदार तथा व्यय अनुवीक्षण नोडल अधिकारी विजयेन्द्र सारथी की उपस्थिति में आज सभा कक्ष में उड़नदस्ता दल एवं स्थैतिक निगरानी दल की बैटक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने बैठक में व्यय अनुवीक्षण दल के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया निर्वाचन कार्य की दृष्टि से अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे खर्च की जानकारी एवं चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराए जाने के लिए आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र कोरबा हेतु उड़नदस्ता दल (एफएसटी), स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) का गठन किया गया है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी सभी दल सक्रिय हो जायेंगे। सभी दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए सावधानी, सख्ती, सतर्कता और शालीनता से कार्य करने के निर्देश दिये गये। सभी चेक पोस्टों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने के साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे वैध एवं अवैध खर्चों की सघन जांच और निगरानी करेंगे। कलेक्टर ने जप्ती के दौरान जप्ती प्रक्रिया की पूर्ण वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिये। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के संवेदनशीलता एरिया में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये है।

राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में त्रुटि नहीं होनी चाहिए-कलेक्टर

अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने तहसीलदार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा कि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए।

कलेक्टर ने पटवारियों पर नियंत्रण रखने और उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को कार्यालयीन कामकाज की व्यवस्था दुरुस्त करने, सुधार लाने और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के समय सीमा के बाहर के प्रकरणों को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा सीमांकन के प्रकरणों में दोनों पक्षों को सूचना देने और ऑर्डर सीट पर हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने डायवर्सन, वृक्ष कटाई, डिजीटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आरबीसी 6-4, नक्शा नवीनीकरण, खसरा नंबरों का पुर्न क्रमांकित आदि कार्यो की तहसीलवार समीक्षा की और लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आंनद डोंगरे, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेंड्रारोड अमित बेक, डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल रजक सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।

पौधा वितरण व राइजोन रूट शूट खरीदी में आर्थिक अनियमितता

तत्कालीन अधिकारियों एसडीओ व रेंजरो को जमा करना होगा 5-5 लाख रुपये

कोरिया। लोकपाल ने मनरेगा के तहत कराये गये पौधरोपण के कार्य मे अनियमितता के मामले में शिकायत बाद जांच में आर्थिक अनियमितता प्रमाणित पाते हुए तत्कालीन उप वनमण्डलाधिकारी समेत तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनेंद्रगढ़ केल्हारी,कुंवरपुर, जनकपुर, बहरासी को 5 -5 लाख रुपये सयुंक्त रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य रोजगार गारंटी कोष में 90 दिनों के भीतर जमा करने का निर्णय पारित करते हुए 1-1हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

गौरतलब है कि 18 अप्रैल 2023 को बैकुंठपुर निवासी चंद्रकांत परागीर ने मनरेगा के लोकपाल के समक्ष वर्ष 2021-22, 2022-23 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में मनरेगा के तहत कराये गये पौधरोपण व हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधों के वितरण में भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायत की थी..जिस पर लोकपाल मलखान सिंह ने वन विभाग से जानकारी मांगी थी ,तथा वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ के द्वारा लोकपाल को जानकारी दी गई थी,वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5 लाख 60 हजार बांस पौधा तैयार करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी,बांस पौधा तैयार करने हेतु बांस राइजोन निविदा दर पर क्रय करना बताया था,इसके साथ ही तुहर पौधा तुंहर द्वार योजना के तहत ग्रामीणों को रोपणी हेतु विभाग द्वारा हितग्राहियों को घर तक पौधा पहुँचाया गया था,मनरेगा के लोकपाल ने जिला पंचायत कोरिया के प्रशासकीय स्वीकृति अवलोकन किया।

लोकपाल ने दस्तावेजों के अवलोकन में पाया कि पौधा हेतु मनेन्द्रगढ़ वनपरिक्षेत्र में 9 लाख 99 हजार रुपये तथा इसी प्रकार बिहारपुर, केल्हारी, जनकपुर, कुंवारपुर व बहरासी वनपरिक्षेत्र हेतु भी 9 लाख 99 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस सम्बंध में लोकपाल ने वन विभाग के अधिकारियों से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था,इसके साथ ही लोकपाल ने स्थल निरीक्षण किया और लोकपाल ने पाया कि हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधों वितरण नही किया गया है। इसके अलावा जांच के दौरान लोकपाल ने राइजोन रूट शूट खरीदी में भी आर्थिक अनियमितता पाते हुए तत्कालीन उप वनमण्डलाधिकारी मनेंद्रगढ़, तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनेन्द्रगढ़, केल्हारी, बहरासी को दोषी पाते हुए 5-5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य रोजगार गारंटी कोष में निर्णय पारित होने के 90 दिवस के भीतर जमा करने का निर्णय पारित किया है, इसके साथ ही 1-1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

अप्रैल एवं मई का राशन एकमुश्त किया जाएगा प्रदान

बलरामपुर। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रचलित राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2024 में पात्रतानुसार एकमुश्त दो माह का चावल (माह अप्रैल एवं मई 2024) का प्रदाय किया जाना है। जिसके लिए खाद्य संचालनालय नवा रायपुर द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2024 का आबंटन जारी कर दिया गया है, परंतु अन्य खाद्यान्न जैसे नमक, शक्कर, चना एक माह (माह अप्रैल) का ही प्राप्त होगा। माह मई 2024 का चना, शक्कर, नमक का वितरण हितग्राहियों को माह मई में प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को दो महीने का खाद्यान्न को सुव्यस्थित वितरण कराने एवं उस पर निगरानी रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है।

करोड़ो की बेशकीमती जमीन पर भू-माफियों का अतिक्रमण

गौरेला पेंड्रा मरवाही। राज्य की भाजपा सरकार एक और जहां भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कहती हैं तो दूसरी और राजस्व विभाग के अधिकारी माफियाओं को संरक्षण देने में लगे है, गौरतलब है की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के राजस्व विभाग में फैला भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के अलावा देश तक सुर्खिया बटोर रहा है, राजस्व के अधिकारी भले ही बदल गए हो लेकिन सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने में अफसरों का रवैया नहीं बदला है इसमें कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदों से अवैध कब्जा को अनदेखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया अतिक्रमण विरोधी अभियान चलवा रहे हैं वहीं कुछ सरकारी कर्मचारी शासकीय भूमि पर दिन रात हो रहे अवैध कब्जा को नजर अंदाज कर अपनी जेबों को गर्म करने में लगे हुए हैं इससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है

जिले के सकोला तहसील अंतर्गत कोरबा से पेंड्रा स्टेट हाईवे रोड में शासकीय भूमि खसरा नंबर 74 रकबा 0.1050 पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा लगभग 25 से 30 डिसमिल बेशकीमती राजस्व की भूमि का बेधड़क अतिक्रमण कर मकान निर्माण किया जा रहा है। तत्कालीन राजस्व अधिकारियों के संरक्षण व वर्तमान में संबंधित अमला के अनदेखी रवैये से अतिक्रमणकारियों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए है,*

अवैध कब्जाधारियों की निगाह करोड़ो के शासकीय भूमि पर फिर जाकर टिक गई है तथा एक बार पुन: वे करोड़ो के राजस्व भूमि पर कब्जा करने की नियत से होड़ मचा रखे है।अतिक्रमण कारी ग्रामीण जिस जमीन को हथियाने में लगे है, भविष्य में उक्त भूमि का उपयोग शासकीय भवनों के अलावा अन्य शासकीय कार्यों के लिए किया जा सकता है। अगर स्थानीय प्रशासन का रवैया ऐसे ही निष्क्रिय बना रहा तो इस 25 से 30 डिसमिल शासकीय जमीन को अवैध कब्जे में जाते देर नही लगेगी, और तब संबंधित अधिकारियों के हाथ- पांव मारने से ज्यादा कुछ फायदा नही होगा तथा करोड़ो की बेशकीमती जमीन अवैध कब्जे की भेंट चढ़ जाएगी। सकोला में रोड से लगे बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने संबंधित

एक ही जगह जिले के खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों के लिए मिलेगी सुविधा

श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लान टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और तायक्वांडो खेल प्रशिक्षण केंद्र का किया गया लोकार्पण

मुंगेली। जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए जिला मुख्यालय स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विभिन्न खेल मैदानों और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने मुखर्जी स्टेडियम में स्केटिंग, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल मैदान और तायक्वांडो प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर श्री राहुल देव के साथ खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे परिचय प्राप्त करते हुए तायक्वांडो और स्केटिंग खेल के प्रदर्शन का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक और कलेक्टर अपने आपको खेलने से रोक नहीं सके और उन्होंने लॉन टेनिस और रस्साकस्सी खेल में हाथ आजमाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही खिलाड़ियों को विभिन्न खेल परिसरों के लोकार्पण के लिए बधाई दी और लाभ उठाने की अपील की।

विधायक श्री मोहले ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सर्व सुविधायुक्त मैदान का निर्माण किया गया है। खेल से शरीर का व्यायाम होता है, मन भी स्वस्थ रहता है, जिससे हम बीमारियों से दूर रहते हैं। साथ ही पढ़ने, लिखने में भी मन लगता है। इसलिए हमें जीवन में खेल को जरूर शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में खेल में भी अपना कैरियर बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में अवसर प्रदान की जाती है। किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए लगन के साथ कड़ी मेहनत करना जरूरी है। उन्होंने स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधा के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की।

कलेक्टर श्री देव ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने अंदर खेलने की भावना जीवित रखें, जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रफुल्लित रहेगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में बॉक्सिंग, बैडमिंटन, मलखंब, बॉस्केटबाल, वालीबाल, टेनिस, एथलेटिक्स, फुटबाल, क्रिकेट और टेबल टेनिस सहित विभिन्न खेलों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आगे और इसमें विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद खेलो इंडिया स्कीम के तहत फुटबाल प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की गई है, जिसमें जिले कई खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान का बेहतर उपयोग करते हुए जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। नगर पालिका मुंगेली के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मोहन मल्लाह ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नियमित खेल खेलने से स्वास्थ्य भी तंदुरूस्त रहता है।

जिले में 40 स्कूल ऐसे जहां 1-1 शिक्षक ही छात्रों की पढ़ाई करा रहे

बेमेतरा। जानकारी हो कि बोर्ड परीक्षाएं आगामी सप्ताह से प्रांरभ होंगी। जिले में स्थानीय स्तर की परीक्षा यानी कक्षा एक से लेकर आठवी, नवमी व ग्यारहवीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के साथ होंगी।

जानकारी हो कि बोर्ड परीक्षाएं आगामी सप्ताह से प्रांरभ होंगी। जिले में स्थानीय स्तर की परीक्षा यानी कक्षा एक से लेकर आठवी, नवमी व ग्यारहवीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा के साथ होंगी। जिले के चार ब्लॉक में संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1146 पद रिक्त हैं, जिसमें बेमेतरा में 262, बेरला 286, साजा 267 और नवागढ़ में सर्वाधिक 331 पद खाली हैं। इसी तरह मिडिल के शिक्षकों के 774 पद खाली हैं।

बेमेतरा ब्लॉक में 208, बेरला 142, साजा 235 व नवागढ़ में 189 पद रिक्त हैं। हाईस्कूल स्तर में बेमेतरा ब्लॉक में 28, बेरला 18, साजा 17 व नवागढ़ में 47 पद खाली हैं। इस वर्ग में शिक्षकों के 110 पदों पर भर्ती नहीं हुई है। हायर सेकंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 428 पद रिक्त हैं। जिले के बेमेतरा ब्लॉक में सभी वर्ग के शिक्षकों के 628, बेरला 512, साजा 650 व नवागढ़ ब्लॉक में 688 पद रिक्त हैं।

हाईस्कूल भी हैं शिक्षकों की तंगी का शिकार

नवागढ़ के ग्राम ठेंगाभाट में संचालित हाईस्कूल में 120 विद्यार्थियों के लिए एक मात्र शिक्षक है। पूर्व माध्यमिक स्कूल ठेंगाभाट में 163 स्टूडेंट्स हैं। यह स्कूल भी एक शिक्षकीय है। 122 छात्रों वाला मिडिल स्कूल चरगंवा, पूर्व माध्यमिक सीबीएससी कन्या स्कूल साजा में 60 छात्राएं हैं पर एक शिक्षक है।

बच्चे थोक में भर्ती पर पढ़ाने वाला केवल एक

शिक्षकों की कमी का शिकार हो रहे स्कूल में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जहां पर बच्चों को थोक में प्रवेश दिया गया है पर उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था तक नहीं की गई है। इन एकल शिक्षकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के प्राथमिक स्कूल सूखाताल में 149, प्राथमिक स्कूल बैहरसरी में 111, प्राथमिक स्कूल खैरझिटी में 175, प्राथमिक स्कूल किरता में 101, प्राथमिक स्कूल गोर्डमर्रा में 111, प्राथमिक स्कूल गाड़ाडीह में 98 विद्यार्थी हैं पर एक ही शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं।

जिले में शिक्षकविहीन स्कूल भी संचालित

जिले में जीरो मैन पॉवर वाले स्कूल का संचालन साल भर जारी रहा है। जिले में जीरो मैन पॉवर वाले खम्हरिया स्कूल, बेमेतरा ब्लॉक में पथर्रीखुर्द, ग्राम मुटपुरी व प्राथमिक शाला सीबीएसई कन्या स्कूल साजा शिक्षक विहीन स्कूल है, जहां पर शिक्षक अटैच कर काम चालाया जा रहा है।

जिले में 149374 स्टूडेंट्स के विपरीत 4997 शिक्षक

जिले के प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल में 149374 विद्यार्थी हैं, जिसमें 71250 छात्र व 78124 छात्राएं हैं। जिले के आत्मानंद स्कूलों में 4046 छात्र व 5273 छात्राएं है, जहां पर संविदा शिक्षक पदस्थ हैं।

निर्माण कार्य का प्रस्ताव अब केएमएल फाइल के रूप में तकनीकी अमलों द्वारा किया जाएगा प्रस्तुत

दुर्ग-कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में मनरेगा के निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक समपन्न

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में मनरेगा के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत मनरेगा द्वारा मुख्य उद्देश्य आगामी 3 वर्षों वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए ग्राम सभा से कार्यों के अनुमोदन उपरांत कार्ययोजना तैयार कर, ग्राम पंचायतवार जीआईएस आधारित कार्ययोजना हेतु केएमएल (कीहोल मार्कअप लैंग्वेज) फाईल तैयार कर, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की संख्या तथा अनुमानित लागत की तत्काल प्रविष्टि करने सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया गया। मनरेगा के तहत निर्माण कार्य का प्रस्ताव केएमएल फाइल के रूप में निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत के 3 वर्ष की कार्ययोजना तैयार कर तकनीकी अमलों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

जिसका उपयोग गूगल अर्थ जैसे अर्थ ब्राउजर में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्थानों को इंगित करने, छवि ओवरले जोड़ने और समृद्ध डेटा को नए तरीकों से प्रदर्शित करने के लिए केएमएल फाइलें बना सकते हैं।

पात्र व्यक्तिगत हितग्राहियों के लगभग 20 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल में बागवानी वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देने के साथ वृक्षारोपण कार्यों को बढ़ावा देने हेतु प्राप्त निर्देश के संबंध में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत के समस्त पात्र व्यक्तिगत लाभार्थी परिवारों के सहमति से लगभग 20 प्रतिशत भूमि क्षेत्रफल को वृक्षारोपण कार्यों से आच्छादित करने हेतु पहल किया जाना है।

इसमें विशेष रूप से बागवानी वृक्षारोपण एवं सड़क किनारे वृक्षारोपण को प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। लिए गए कार्यों की संख्या, कार्य में लगाए गए पौधों की संख्या एवं कार्य के लिए उपयोग की गई भूमि का क्षेत्रफल एमआईएस में दर्ज किये जाने के भी निर्देश दिए गए है। उक्त बैठक में एसडीओ (आरईएस), सब इंजिनियर (आरईएस), कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा उपस्थित रहे।

चुन्नीलाल साहू सहित नौ सांसदों का टिकट कटा

छत्तीसगढ़ में टीम भाजपा-11 की घोषणा

महासमुन्द से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी होंगी भाजपा प्रत्याशी

रायपुर। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भाजपा की पहली सूची में कुल 195 सीटों के लिए नाम तय किए गए हैं। इन सीटों में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और दो पूर्व सीएम समेत कुल 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में भाजपा ने अपने उम्मीदवार तय कर दिये हैं।

रायपुर लोकसभा सीट

रायपुर लोकसभा सीट से इस बार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हैं। वे रायपुर के दक्षिण विधानसभा से जीतते आये हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास को रिकॉर्ड मतों से हराया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को करीब 66 हजार वोटों से पछाड़ा है।

दुर्ग लोकसभा सीट

दुर्ग लोकसभा सीट से पार्टी ने एक बार फिर से विजय बघेल पर भरोसा जताया है। 2019 के चुनाव में भी विजय बघेल दुर्ग लोकसभा से चुनाव जीत कर आए थे। 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पाटन विधानसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

सरगुजा लोकसभा सीट

सरगुजा लोकसभा सीट से पार्टी ने चिंतामणी महराज को टिकट दिया है। महराज ने हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया है। सामरी विधानसभा से वे दो बार के विधायक रहे हैं। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भाजपा प्रवेश कर लिया था।

रायगढ़ लोकसभा सीट

रायगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी ने राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया है। राठिया भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। राठिया वर्ष 1995 से 2000 तक निर्विरोध उपसरपंच ग्राम पंचायत छर्राटांगर रहे। वर्ष 2000 से 2005 तक जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2005 से 2010 तक जनपद पंचायत घरघोडा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्ष 2010 से 2015 तक जिला पंचायत सदस्य रहे हैं।

जांजगीर लोकसभा सीट

जांजगीर लोकसभा सीट से पार्टी ने कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया है। जांगड़े 2023 से नवीन जिला सक्ती की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत मसनियां कला की दो बार की सरपंच भी हैं।

बिलासपुर लोकसभा सीट

बिलासपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने तोखन साहू को उम्मीदवार बनाया है। तोखन साहू 2013 में प्रथम बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे 2015 में संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन रहे हैं।

राजनांदगांव लोकसभा सीट

राजनांदगांव लोकसभा सीट से पार्टी ने संतोष पांडेय को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीतकर आए थे। एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें मौका दिया है।

बस्तर लोकसभा सीट

बस्तर लोकसभा सीट से पार्टी ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। महेश कश्यप पूर्व सरपंच और अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष के पद पर हैं। वे सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

कोरबा लोकसभा सीट

कोरबा लोकसभा सीट से पार्टी ने सरोज पांडेय को उम्मीदवार बनाया है। सरोज पांडेय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ ही वे राज्यसभा सांसद भी रही हैं। इससे पहले, वह दुर्ग से 15वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं और छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्य भी थीं। सरोज पांडेय ने पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता के रूप में कार्य किया फिर उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव का पद संभाला। सरोज के नाम एक ही समय में मेयर, विधायक और सांसद का पद संभालने का विश्व रिकॉर्ड है।

कांकेर लोकसभा सीट

कांकेर लोकसभा सीट से पार्टी ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया है। भोजराज नाग 2014 में प्रथम बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे छ.ग. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ कर जनजाति समाज के उत्थान और नशामुक्ति के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

महासमुंद लोकसभा सीट

महासमुंद लोकसभा सीट से पार्टी ने रूपकुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी 2013 से 2018 में बसना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की विधायक थी। रूपकुमारी बसना विधानसभा क्षेत्र के धनापाली गांव की रहने वाली है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत महासमुंद जिला पंचायत सदस्य के रूप में की थी, साथ ही भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। वर्तमान में वे छत्तीसगढ की एक मात्र महिला जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने एमए तक की शिक्षा पूरी की है। रूपकुमारी पैशे से किसान परिवार से हैं।

एक करोड़ के लालच में सांप से कटवाकर नानी की हत्या

बीमे की रकम हड़पने लालची नाती का लोमहर्षक कारनामा,

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से चौका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के पखांजूर में करीब नौ माह पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया था। पहले तो इस मौत को स्वाभाविक मान लिया गया था लेकिन जांच में जब इसके पीछे हत्या की साजिश का खुलासा हुआ तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। महीनों तक चले जाँच, पड़ताल और पूछताछ में पुलिस अब न सिर्फ हत्या की वजह बल्कि उस हत्यारे तक भी पहुंच चुकी हैं। पूरा मामला पैसे से जुड़ा था। बुजुर्ग महिला की हत्या रकम हथियाने के लिए की गई थी। वही हत्यारा अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गया था लेकिन वह कानून की नजरों से ज्यादा दिनों तक नहीं बच सका। कांकेर पुलिस प्रेस कांफ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है।

जानकारी के मुताबिक़ बुजुर्ग महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही नाती ने की थी।

दरअसल बुजुर्ग नानी के नाम पर एक करोड़ रुपये का बीमा था और यही रुपये हत्या की वजह भी बने। लालची नाती बीमा की रकम हथियाना चाहता था। इसके लिए उनसे नानी की हत्या की साजिश रची। उसने एक सपेरे को अपने इस साजिश में शामिल किया और नानी को जहरीले सांप से दंश दिलाने के लिए उसे करीब डेढ़ लाख रुपये भी दिए। नाती नानी की मौत के बाद बीमा की राशि क्लेम करने में सफल भी रहा था। लेकिन पुलिस ने उसकी इस पूरे साजिश का पर्दाफ़ाश कर दिया है।

दाल की बोरियों में छिपा पांच करोड़ का गांजा जब्त

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने बड़े गांजा तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 334 किलो गांजा जब्त किया है। ओडिशा से तस्करी कर लाए जा रहे इस गांजे को छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाना था। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग पांच करोड़ बताई जा रही है।

कांग्रेस ने जारी की लोस चुनाव के लिए, राजनांदगांव से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव

भूपेश बघेल | ताम्रध्वज साहू | ज्योत्सना महंत | विकास उपाध्याय | शिव डहरिया | राजेन्द्र साहू

रायपुर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 39 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से छह नामों का एलान किया है जिसमें कोरबा से ज्योत्सना महंत को उम्मीदवार बनाया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, रायपुर से विकास उपाध्याय, जांजगीर चांपा से शिवकुमार डहरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। राजेन्द्र साहू को पार्टी ने दुर्ग से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी।

लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नामों का एलान किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर उम्मीदवारों के नामों का एलान किया। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार सामान्य वर्ग से हैं।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया है जिसमें 15 जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं जबकि 24 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एससी,एसटी और ओबीसी समुदाय से आते हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ से छह उम्मीदवारों को मौदान में उतारा है। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर आजादी के बाद से अब तक कुल 17 चुनाव हो चुके हैं। राजनांदगांव निर्वाचन क्षेत्र में 1952 से लेकर 1999 तक 13 बार चुनाव हुए। जिनमें से ज्यादातर नतीजे कांग्रेस के ही पक्ष में रहे हैं। साल 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन से बने छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के बाद से यहां 2007 में एक उपचुनाव के अलावा तीन लोकसभा चुनाव हुए हैं। 1999 के बाद से 2007 के उपचुनावों के अलावा सभी चुनावों (1999, 2004, 2009, 2014 और 2019) में बीजेपी ने सीट पर कब्जा करने में कामयाब रही है।

सरायपाली क्षेत्र में मिले प्रदेश में सर्वाधिक 133 कुष्ठ रोगी

एक वर्ष से नहीं हुआ कोई जनजागरूकता कार्यक्रम

सरायपाली। ब्लॉक के कुष्ठ मरीजों की संख्या डराने वाली है। रोगियों द्वारा रोगों को छिपाने और जागरूकता के अभाव में यह संख्या अन्य ब्लॉक, राज्य व देश की अपेक्षा काफी अधिक है, सरायपाली ब्लॉक में 3.5 प्रतिशत कुष्ठ रोगी हैं, जबकि देश में इसकी संख्या 0.45 है। छत्तीसगढ़ में 2.8 और महासमुंद में 3.31 प्रतिशत है। कुष्ठ रोग भी दो तरह के होते हैं। कम दाग वाले पीबी (पाउसी बेसिलेरी कैटेगिरी) में आते हैं। जिनके शरीर में असंक्रामक अल्प जीवाणु जनित रोग पाया जाता है। इनके लिए 6 माह का कार्स रहता है। अधिक दाग वाले संक्रामक श्रेणी में आते हैं। इसे पीबी मल्टीबेसिलरी कहते हैं। इनके शरीर में जीवाणु की संख्या भी अधिक होती है। इन्हें एक वर्ष दवाई सेवन करना पड़ता है।

सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कुछ रोगियों की संख्या10 कम है। कुछ रोग पर लगाम कसने स्वास्थ्य विभाग को डोर-टू-डोर सर्वे करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सर्वे में पहुंचने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम को बिना झिझक के अगर किसी के शरीर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रही जानकारी जैसे लक्षण और संकेत लगें तो उन्हें एक बार जरूर परीक्षण कराना चाहिए। 2023-24 में कुष्ठ रोग के लिए एक बार भी शिविर न लगाए जाने से जन जागरूकता का अभाव लोगों में बहुत देखा जा रहा है। सरायपाली में कुष्ठ रोगियों की संख्या काफी अधिक है। प्रति 10 हजार की संख्या में कुष्ठ मरीजों की गिनती की जाती है।

भारत में कुष्ठ पीड़ित मरीजों की संख्या 0.45 प्रतिशत है। जबकि, सरायपाली में 3.51 प्रतिशत कुष्ठ के पीड़ित मरीज हैं। बता दें कि पिछले वर्ष अप्रैल 2022 व मार्च 23 तक अल्प जीवाणु जनित कुष्ठ से पीड़ित 66 लोग थे इस तरह कुल 143 पीड़ित व्यक्ति पाए गए थे। अप्रैल 2023 और फरवरी 24 में कम संक्रमित में 62, अधिक संक्रमित 71 कुल 133 पॉजिटिव मरीज फरवरी तक पाए गए हैं। हालाकि, पिछले वर्ष के आंकड़े मार्च तक के थे और अभी एक माह के आंकड़े आने शेष है।

कुष्ठ संक्रामक बीमारी है, जो विशेष रूप से त्वचा आंख, तंत्रिका को प्रभावित करता है। यह रोग मायक्रोबैक्टेरियम लेप्री नामक जीवाणुओं के कारण होता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों में लक्षणों के रूप में त्वचा में घाव, गांठ आदि दिखाई देते हैं। यह रोग पीड़ित व्यक्ति द्वारा खांसने व छींकने से फैलता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों में त्वचा सामान्य से हल्की होती है। इसके लक्षणों में कमजोर मांसपेशियां, दानेदार उभार जो कि प्राय: कान में गले के पास रहते हैं। उंगलियों के पोरों में सुन्नपन और बैक्टिरिया की संख्या बढ़ने से घाव और अंगों की विकृति देखने को मिलती है। सही समय पर इलाज शुरू नहीं किया जाए तो त्वचा, हाथ, पैर, आंख और नर्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

उपचार में दी जाती है एंटीबायोटिक्स औषधि

कुष्ठ रोग के फैलाव की स्थिति के आधार पर इसका उपचार 6 माह और 12 माह तक हो सकता है। इसमें मरीजों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है। दवा शुरू करते ही बीमारी का फैलाव रूक जाता है। कुष्ठ रोग के कारण त्वचा हाथ, पैर, आंख और तंत्रिका प्रभावित होते हैं। उसे आगे नुकसान होने से बचाया जा सकता है, इसलिए इसका उपचार तत्काल और दवा को पूरा कोर्स लेना चाहिए। कुष्ठ रोग का जांच उपचार सभी शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क उपलब्ध है। इसके लिए दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती है।

बिना लाइसेंस के चल रहा था स्वास्तिक हॉस्पीटल, सील

मुंगेली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने निजी अस्पताल में छापामार कार्रवाई कर स्वास्तिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को सील किया है। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से इस निजी अस्पताल का संचालन किया जा रहा थाण् नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग के मना करने के बावजूद ऑपरेशन किया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के दौरान डॉक्टर, जरूरी संसाधन और प्रशिक्षित स्टॉफ नहीं थे, फिर भी नसबंदी के लिए मरीजों को भर्ती कराया गया था॥

कलेक्टर राहुल देव के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 अंतर्गत स्वास्तिक हेल्थ केयर हास्पिटल, रामगढ, जिला मुंगेली का औचक निरिक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान हास्पिटल में कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं था। हास्पिटल में अप्रशिक्षित स्टॉफ से मरीजों का उपचार किया जा रहा था। हास्पिटल के वार्ड में कुल 5 मरीजों को भर्ती कर रखा गया था। जिनका ऑपरेशन किया जाना था। पूर्व में हास्पिटल संचालक को ऑपरेशन नही करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद भी हास्पिटल प्रबंधन के जरिए ऑपरेशन किया जा रहा था। निरीक्षण टीम ने बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव के लिए इनवायरोकेयर अनुबंध, फ ायर सेफ्टी एनओसी की जानकारी चाही, जिसे हास्पिटल प्रबंधन ने उपलब्ध नहीं कराया। ऑपरेशन के लिए उपस्थित भर्ती मरीजों का केशसीट जब्त किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 और नियम 2013 अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लघंन करने, चिकित्सक की अनुपस्थिति में हास्पिटल संचालित करने और अवैध रूप से ऑपरेशन संचालित करने के कारण डॉ. देवेन्द्र पैकरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार की उपस्थिति में हास्पिटल के ऑपरेशन थियेटर को आगामी आदेश तक सीलबंद करने के साथ ही ओपीडी और आईपीडी सेवा प्रतिबंधित की गई है।

कलेक्टर वर्मा ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया

खैरागढ़। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के लिए खैरागढ़ पिपरीया स्थित एफसीआई गोदाम में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया।

उन्होने संपूर्ण स्थल के सुरक्षा के मद्देनजर बारीकी से निरीक्षण करते हुए लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने के दौरान सामग्री वितरण, सामग्री मिलान, पार्किंग, स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ टंकेश्वर प्रसाद साहू, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग ललित वाल्टर तिर्की, जिला खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक, नयाब तहसीलदार जालबांधा मोहन लाल झारिया एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरा, मतपेटी, ईव्हीएम वितरण केंद्र व मतगणना स्थल तक सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग, साफ-सफाई, विद्युत, अग्निरोधक यंत्र, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था, ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा मीडियाकर्मियों के लिए उचित स्थल का भी निर्धारण किया गया।

लापरवाही, सहायक समिति प्रबंधक निलंबित

खैरागढ़। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देश के बाद धान उपार्जन केन्द्र झुरानदी में लापरवाही बरतने के कारण सहायक पंजीयक ने जांच उपरांत सहायक समिति प्रबंधक प्रकाश कुमार चंदेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर रणजीत वर्मा लिपिक सेवा सहकारी समिति झुरानदी को धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी के साथ-साथ समिति के समस्त कार्यों के लिए अधिकृत किया गया है।

किसान के परिवार को माहभर बाद भी नहीं मिला न्याय

पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पूर्व विधायक उतरेगी सडक़ पर

अंबागढ़ चौकी। प्रताडऩा से तंग आकर एक महीने पहले फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले डोंगरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीटिकुल के किसान लक्ष्मण साहू के मामले में अब तक पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ न तो जुर्म पंजीबद्ध किया है और न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की। जबकि किसान द्वारा मृत्यु से पूर्व छोड़े गए आत्महत्या नोट में प्रताडऩा का उल्लेख करते पत्र में प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।

पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से क्षुब्ध एवं आक्रोशित मृतक की पत्नी ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए एक माह का अल्टीमेटम दिया है अन्यथा परिवार सहित जिला मुख्यालय में जिला कार्यालय के समक्ष शासन-प्रशासन के विरोध में सडक़ में उतरने की चेतावनी दी।

ग्राम खुर्सीटिकुल निवासी हेमीनबाई साहू ने राजनांदगांव कलेक्टर व एसपी को दिए गए 30 जनवरी को अपने ज्ञापन में बताया है कि उसके पति लक्ष्मण साहू ने 5 जनवरी को ग्राम खुर्सीटिकुल में गौठान के समीप एक बबूल वृक्ष में प्रताडऩा से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पत्नी ने कलेक्टर व एसपी को संबंधित पत्र में उल्लेख किया है कि उसके पति ने मृत्यु से पूर्व अपने पास एक आत्महत्या नोट छोड़ा है। जिसमें प्रताडऩा के कारणों के साथ प्रताड़ित करने वाले आरोपी का नाम भी स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन घटना के एक माह गुजर जाने के बाद भी आरोपी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

समय सीमा में संयंत्र नहीं लगाने वाले उद्योगों को तीन दिन के भीतर जारी करें नोटिस: देवांगन

- **प्रदेश में शीघ्र की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी**
- **बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के महाप्रबंधक को शो-काज नोटिस जारी**

रायपुर। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग के नाम पर जमीन लेने के लिए बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। गुरुवार को सर्किट हाउस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधकों की बैठक लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री कमल सिंह मीणा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, संचालक उद्योग पी. अरूण प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर संचालक उद्योग श्री अलोक त्रिवेदी, श्री प्रवीण शुक्ला, श्री संतोष भगत सहित जिलों से आए अधिकारी उपस्थित थे।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधको को निर्देश देते हुए कहा की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो, हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। उद्योग मंत्री ने कहा कि जमीन आबंटन के बाद भी अगर उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, ऐसे उद्योगों के अधिकृत व्यक्ति को नोटिस जारी करें और अगर फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आबंटन निरस्त करने की कारवाई करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग-धंधा सहायक हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदको स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। लोन पास करने के नाम पर बैंकर्स हितग्राहियों बैंकों के बार-बार चक्कर न लगवाएं। उद्योग विभाग के अधिकारी इस बात के विशेष ध्यान रखें।

नए जिलों में योजना के क्रियान्वन पर विशेष ध्यान दें

मंत्री श्री देवांगन ने नए जिलों में भी सभी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नए जिलों में भी आवेदनों के निराकरण के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करे। कैबिनेट मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, सभी 18 ट्रेड के हितग्राहियों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिलवाए।

उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारी शासन के विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करे, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से कार्य मिले, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी एवं मैदानी क्षेत्रों पदस्थ अधिकारी बेहतर कार्य करें।

उद्योग मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में स्थापित नवीन उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की और फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, उद्योगों के लिए किए गए एम.ओ.यू. की प्रगति, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों, वाष्पयंत्र निरीक्षणालय कार्यों, पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह,165 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

सारंगढ़ बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 7 मार्च को सुबह 11 बजे से लगभग 165 जोड़ी वर वधु का सामूहिक विवाह जिला मुख्यालय सारंगढ़ के खेल भांठा मैदान में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम अतिथि विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े, जिला कलेक्टर धर्मेश साहू, परियोजना निर्देशक हरिशंकर चौहान, जिला चिकित्सा अधि. डॉ एफआर निराला, नपाध्यक्ष सोनी अजय बंजारे, एसडीएम आईएएस वासु जैन, जनपद उपाध्यक्ष नेताम, पार्षद सरिता गोपाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोल्डी नायक के साथ अन्य अधिकारी और नेताओं की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ।

कलेक्टर श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से वर वधु के जोड़े को 50 हजार पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि और सामग्री शामिल है। साहू जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सशक्तिकरण मोदी की गारंटी है। भारत की नारी शक्ति विकसित भारत की शक्ति स्तंभ है। भारत की नारी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। जिसके तहत जन धन योजना के तहत स्वच्छता समूह की महिलाओं ने खाते खुलवाए हैं। इसके साथ ही इन सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से मदद उपलब्ध कराई गई है। आज महिला स्व सहायता नहीं राष्ट्र सहायता समूह है, जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है, जिसमें बिना गारंटी के ऋण लेकर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। छग सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना भी महिलाओं के हित के लिए प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना का शुभारंभ ठीक 11 बजे हुआ, जहां सैकड़ों बाराती बाजे गाजे के साथ गढ़ चौक से आतिश बाजी करते हुए निकले नोडल विभाग महिला बाल विकास के साथ जनप्रतिनिधियों, समाज प्रमुख और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक वेदी पर चार वर वधू आहुतियां दे रहे थे। मंच पर विराजित पंडित द्वारा मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, जिन्हें उपस्थित वर और वधू उनके निर्देश के अनुरूप कार्य कर रहे थे। वर-वधू उनके परिवार एवं बारातियों की भोजन की व्यवस्था भी सरकारी रहा। वर-वधु को 21 हजार का चेक व 29 हजार रुपया की सामग्री दिया गया। इस विवाह के लिए वर वधु की जोड़ी और उनके परिवार को सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए महिला बाल विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंच संचालन प्रियंका गोस्वामी कर रहीं थीं।

नपं बिलाईगढ़ अध्यक्ष चुनाव के लिए सम्मेलन 12 को

सारंगढ़-बिलाईगढ़। नपं बिलाईगढ़ में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 12 मार्च का समय एसडीएम द्वारा निर्धारित किया गया है ।

नपं बिलाईगढ़ में अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु 12 मार्च को सम्मेलन हेतु जिला कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम बिलाईगढ़ के द्वारा निर्धारित किया गया है। नपं में विगत 2 वर्षों से अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। मनोनीत कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चलाया जा रहा था इसके पूर्व नगर पंचायत बिलाईगढ़ का अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाने के बाद कांग्रेस सरकार ने एक पार्षद को कुछ दिनों के लिए कार्य वाहक अध्यक्ष बनाया था। ज्ञात हो कि हाई कोर्ट से तीन बार स्टे लाते हुए कार्य वाहक अध्यक्ष के रूप में लगातार कार्य किया जा रहा था, किंतु प्रदेश में सरकार बदलने के बाद प्रदेश भाजपा सरकार ने 19 फरवरी 24 को रिक्त पद की पूर्ति होने तक नपं बिलाईगढ़ के वार्ड क्र. 13 के पार्षद रामनारायण देवांगन को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने एसडी एम डॉ स्निग्धा तिवारी को इस आशय हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए सम्मेलन 12 मार्च को समय सुबह 11 बजे करने हेतु आदेशित किया है।

पोषक मिलेट्स बार का बच्चों में वितरण

सारंगढ़। शाप्रा, माशाला सुखापाली में अंतरराष्ट्रीय पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स बार का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत छग शासन द्वारा छग के बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए नया कदम उठाया गया है। छग शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने पोषक तत्वों से युक्त मिलेट्स बार को प्राथमिक /माध्यमिक स्कूलों में बांटने के लिए भेजा है। मिलेट्स बार एक बिस्किट के रूप में है, इसे बच्चों को स्कूल पहुंचने पर नास्ते के रूप में दिया जाएगा। ज्ञात हो कि मिलेट्स बार फोर्टी फाइड एनर्जी, डेंस फूड है। जिसमें तेरह वैरायटी मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय पोशाक अनाज बाजारा, रागी, कुटकी, संवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो के गुण मौजूद रहते हैं साथ व्हीटफ्लोर, वेजिटेबल फैट, सोया फ्लोर, फिंगर मिलेट,व्हीटब्रान,व्हीट प्रोटीन, साइकाइट्रिक साल्ट, इवर्ट शुगर, माल्ट एक्ट्रेस से बनाया गया है।

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के समक्ष हुआ भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यशाला

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के रायपुर शाखा के दल ने कार्यशाला किया। रायपुर शाखा के बीआईएस प्रमुख श्री सुमित कुमार ने एसपीओ सचिन कुमार और एसपीसी विकास मृधा के सहयोग से पीपीटी प्रस्तुतीकरण में बताया कि किसी भी वस्तु का गुणवत्ता उसके क्वालिटी, क्षमता, गुण के आधार पर तैयार होता है, जिसमें मानक के रूप में निर्धारण किया जाता है। सभी विभाग को उपकरण, मशीन, उत्पाद आदि की खरीदी के समय भारतीय मानक दर का उपयोग कर किया जाना चाहिए। केन्द्र और राज्य और जिला प्रशासन के अधीन मानक दर निर्धारण के लिए अलग-अलग स्तर पर जांच दल, विभाग, एजेंसी होते हैं, जो जांच करते हैं।

श्री सुमित कुमार ने बताया कि पानी के बोतल से लेकर हर एक उत्पाद में चिपके या प्रिन्टेड जानकारी से उस उत्पाद के मानक के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई उत्पाद आईएस मार्क है तो वह नंबर, प्रतीक आदि से उत्पाद के साथ जुड़ा होगा। यदि कोई गहने का दुकानदार बिना मार्क और मार्क वाले गहनों के बीच ज्यादा अंतर बताता है तो यह गलत है। मार्क और बिना मार्क के गहने के बीच 40 रूपए का अंतर होता है। इसी प्रकार गहने में मार्क के साथ वर्तमान में 6 नंबर अंकित होगा। व्यवसायी कोई पदार्थ में भारतीय मानक ब्यूरो से यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और मार्क का उपयोग कर रहा है तो वह मानक कानून के तहत आरोपी होगा। श्री सुमित कुमार ने कहा कि सभी विभागों से जुड़े उत्पाद, उपकरण आदि के लिए मानक तय है और उत्पादों के लिए केन्द्र सरकार ने जांच के लिए विभाग भी तय कर रखे हैं। व्यवसायी के उत्पाद, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस आदि के बारे में वेबसाइट https://www.bis.gov.in/ बीआईएस डॉट जीओवी डॉट इन से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिव्या अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर मोनिका वर्मा, एसडीएम श्री वासु जैन, डॉ. स्निग्धा तिवारी, उप संचालक कृषि श्री आशुतोष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की निकाली गई पर्ची

146 यात्रियों का किया गया चयन

कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना श्री रामलला दर्शन योजना अन्तर्गत आज कोरबा जिले से अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्रियों का चयन किया गया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संबित मिश्रा की मौजूदगी में आवेदन करनेवाले तीर्थ यात्रियों का चयन जनप्रतिनिधियों और आवेदकों के माध्यम से पर्ची निकालकर किया गया। जिले में कुल 327 लोगों ने आवेदन किए थे, जिसमें से 146 का चयन किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रामलला दर्शन योजना अंतर्गत पात्र तीर्थ यात्रियों की पर्ची लॉटरी पद्धति से निकाली गई। ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 272 लोगों ने और शहरी क्षेत्र से 55 लोगों ने आवेदन किया था। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से 110 और शहरी क्षेत्र से 36 का चयन रामलला दर्शन योजना के लिए किया गया है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने तीर्थ यात्रियों के चयन के दौरान पारदर्शिता अपनाते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्री सिनीवाली गोयल ने बताया कि रामलला दर्शन योजना के लिए चयनित तीर्थ यात्रियों को आगामी दो दिवस 08 मार्च तक चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चयनित तीर्थ यात्रियों द्वारा पूर्व में जहां आवेदन किया गया था वहां चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से 27 और शहरी क्षेत्र से 10 का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयनित तीर्थ यात्री द्वारा अयोध्या नहीं जाने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों का चयन किया जाएगा।

11 मार्च को बिलासपुर से रवाना होंगे तीर्थ यात्री -

कोरबा जिले से चयनित रामलला दर्शन योजना अंतर्गत चयनित सभी 146 यात्री 11 मार्च को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 01 बजे रवाना होंगे। 40 यात्रियों के पीछे 01 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले तीर्थ यात्री अपने साथ एक सहायक रख सकेंगे।

पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू सहित चौलेश्वर चंद्राकर ने छोड़ी पार्टी

लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका

रायपुर। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में दल-बदल तेज हो गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं में पूर्व चुन्नी लाल साहू और जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर का नाम शामिल है। चुन्नी लाल साहू ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद चुन्नी लाल साहू ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। चर्चा है कि वे शीघ्र ही भाजपा प्रवेश करेंगे।उनके साथ जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चोलेश्वर चंद्राकर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ज्ञात हो कि इस साल उसने अकलतरा से टिकट की दावेदारी की थी पर उसे टिकट नहीं मिला। लंबे समय से वे कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। चुन्नीलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस छोड़ दिया हूं आगे क्या करेंगे इसकी जानकारी शीघ्र देंगे। लोकसभा चुनाव के पूर्व इस तरह पार्टी छोड़ देने से कांग्रेस को नुकसान है।

छत्तीसगढ़ के राजस्व न्यायालय होंगे कम्प्यूटरीकृत और इंटरनेट कनेक्टिविटी से लैंस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम होगा। इसके तहत राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लैण्ड रिकार्ड का डिजीटीलाईजेशन का काम होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री भुवनेश यादव ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक यह निर्णय लिया गया है।

बैठक में राज्य के 572 राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) के लिये कंप्यूटर, प्रिंटर तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदाय किया जाएगा और 18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये जिलों को आबंटन करने का निर्णय लिया गया।

कोरबा लोस चुनाव में पहली बार दो महिला प्रत्याशी आमने-सामने

कोरबा। ज्योत्सना महंत पर कांग्रेस हाईकमान ने लगातार दूसरी बार विश्वास जताते हुए कोरबा लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। ज्योत्सना कांग्रेस के दिग्गज नेता व नेता प्रतिपक्ष डा चरण दास महंत की धर्मपत्नी हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में डा चरण दास सक्ती विधानसभा विधायक चुने गए थे और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 2019 में डा महंत की जगह ज्योत्सना को टिकट दी गई और वे पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे को परास्त कर 26 हजार मतों से जीती थीं।

शुक्रवार को 36 सीटों की पहली सूची जारी हुई। इसमें कोरबा से ज्योत्सना महंत का नाम भी शामिल रहा। जिस ढंग से ज्योत्सना क्षेत्र में सक्रिय थी, उससे यह अंदाजा लग गया था, इस बार भी उनकी मजबूत दावेदारी है। अब कोरबा लोकसभा में तस्वीर साफ हो गई है। इस बार सरोज व ज्योत्सना के बीच सीधे मुकाबला होगा। पहले ही यहां से भाजपा राज्य सभा सदस्य सरोज पांडेय को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पहली बार कोरबा में दो

महिलाएं आमने- सामने होंगी। यहां बताना होगा कि अखंड जांजगीर लोकसभा में वर्ष 1957 से चुनाव हो रहा। इस बीच कांग्रेस व भाजपा दोनों ने महिला नेत्रियों को मौका दिया, पर ऐसा नहीं हुआ कि दोनों राष्ट्रीय दल ने एक साथ महिला नेत्रियों को मैदान में उतारा हो। सबसे पहले कांग्रेस ने वर्ष 1957 में मिनीमाता अगमदास गुरू को प्रत्याशी बनाया और वह सांसद बनी। इसके बाद वर्ष 1962, 1967 व वर्ष 1971 में चुनाव लड़ी और लगातार जीत हासिल की। वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटलबिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया और वे सांसद निर्वाचित हुई। परिसीमन के बाद वर्ष 2009 में कोरबा लोकसभा अस्तित्व में आया और भाजपा ने पुनः करूणा शुक्ला को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन इस बार डा चरण दास महंत से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

कोरबा लोकसभा अंतर्गत आठ विधानसभा रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली- तानाखार, मरवाही, भरतपुर-सोनहत, बैकुंठपुर व मनेन्द्रगढ़ हैं। इनमें रामपुर विधानसभा सीट में ही कांग्रेस के फूलसिंह राठिया विधायक हैं। जबकि पाली-तानाखार विधानसभा सीट से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर सिंह मरकाम विधायक है। शेष छह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है।

नगर निगम की सभापति के खिलाफ भाजपा पार्षदों अविश्वास प्रस्ताव

जगदलपुर। नगर निगम की सभापति के खिलाफ भाजपा पार्षदों की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 11 मार्च को वोटिंग होनी है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी तैयारियों के लिए दो पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन के साथ ही रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। दोनों ही नेता इस नियुक्ति के साथ ही कांग्रेसी पार्षदों के संपर्क में आ गए हैं।

बताया जा रहा है कि नियुक्ति के साथ ही सोमवार को पर्यवेक्षकों ने

सभी पार्षदों ने वन टू वन बातचीत की है। निगम में संख्या बल के हिसाब से कांग्रेसी पार्षदों की संख्या ज्यादा है। अभी सदन में कांग्रेस के 29 पार्षद हैं। इस बीच चर्चा यह भी है कि कुछ पार्षद सभापति से नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने का काम पर्यवेक्षकों को सौंपा गया है। वोटिंग के दौरान कांग्रेस के लिए एक-एक वोट कीमती होगा।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस संगठन ने सभापति की कुर्सी को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम चुनाव में अभी लगभग 9 महीने का वक्त बाकी है और उससे पहले कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि सभापति की कुर्सी उसके हाथ से निकले। इस बार राज्य में सरकार भी नहीं है इसलिए कांग्रेस के सामने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना एक बड़ी चुनौती है।

महापौर के खिलाफ वोटिंग नहीं हो पाई थी

पिछली बार भाजपा पार्षदों ने महापौर सफीरा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसके लिए तय तिथि पर कांग्रेसी पार्षद शहर से बाहर थे और कोरम पूरा नहीं होने की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई थी। इस बार ऐसी स्थिति बनती नहीं दिख रही है। दरअसल 11 तारीख को ही निगम की सामान्य सभा भी है इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेसी सदन में ही मौजूद रहेंगे और वोटिंग भी होगी।

फिर भागने की तैयारी में कांग्रेस

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडेय ने कहा कि कांग्रेस इस बार फिर अविश्वास प्रस्ताव से भागने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि जानबूझकर बजट की तारीख 11 मार्च तय की गई। अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पांडेय ने कहा कि कांग्रेस अपने ही जाल में फंसती जा रही है।

लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, पूर्व विधायक भाजपा में हुए शामिल

कांकेर। कांग्रेस के पूर्व विधायक मंतूराम पवार फिर भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। 2014 में अंतागढ़ में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्यासी रहे मंतूराम पवार ने अपना नामांकन वापस ले उपचुनाव में भाजपा को वाकओवर दे दिया था। इस घटना के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बाहर किया था।

जिसके कुछ माह बाद वे भाजपा की सदस्यता ले ली थी और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में अंतागढ़ से भाजपा के टीकट की दावेदारी भी की थी पर भाजपा ने उन्हें टिकट न देते हुए विक्रम उसेंडी को टिकट दिया था। इस चुनाव में भाजपा अंतागढ़ विधानसभा का चुनाव हार गई थी साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई।

इसके बाद से पूर्व विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। उनके और दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना पखांजूर में मामला भी दर्ज कराया था, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें बाहर कर दिया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पूर्व विधायक फिर भाजपा में लौट आए है। उन्होंने बताया की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप तो लगते ही रहते है।

उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मंतूराम पवार 2023 के चुनाव में पवार समथर्क दल नाम से संगठन बना अंतागढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें कुल 13 हजार मत मिले। अब वे फिर समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए है।

आयुष्मान कार्डधारी मरीज से लिया नकद, हाईटेक सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने राज्य नोडल को पत्र

भिलाई। आयुष्मान कार्डधारी मरीज से दाखिल होने पर नकद लिए जाने की शिकायत हाईटेक सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर के खिलाफ की गई थी। इस मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने जांच के बाद हाईटेक हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर को शुक्रवार को पत्र लिखा है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शिकायत कर्ता रवि कुमार सोनकर ने अपनी मां पूनम सोनकर को उपचार के लिए हाई टेक सुपर स्पेशिलिटी हास्पीटल, भिलाई में दाखिल किया। उनका उपचार आयुष्मान कार्ड से किया जाना था, परंतु चिकित्सालय ने उपचार के दौरान आयुष्मान कार्ड के उपचार के अतिरिक्त नकद राशि ली गई।

साक्ष्य भी किया पेश

शिकायत करने वाले ने सबूत के तौर पर नकद राशि देने का वीडियो रिकार्डिंग भी उपलब्ध करवाया। इससे शिकायत उनकी पुख्ता हो रही है। इस तरह की शिकायत दूसरे अस्पतालों से भी लगातार आ रही है। अलग-अलग बहाना से नकद लिया जा रहा है। शासन का कोई अधिकारी अस्पताल में नैतान नहीं रहता है, जिसे मरीज के परिजन हकीकत बता सकें।

स्पष्टीकरण के लिए दिया पत्र

शिकायत मिलने पर आयुष्मान से जुड़े जिला के अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र के माध्यम से चिकित्सालय को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पत्र दिया। इस पर चिकित्सालय ने नकद राशि लिए जाने की पुष्टि की।

लापरवाही बरती अस्पताल प्रबंधन ने

स्पष्टीकरण में नकद राशि लिए जाने की पुष्टि होने से, यह साफ हो गया कि चिकित्सालय ने योजना के कृयांवयन में लापरवाही बरती गई है व मरीज से नकद राशि जमा करवाई गई है।

कार्रवाई करने लिखा पत्र

डॉक्टर अनिल शुक्ला ने योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्य नहीं करने व हितग्राही के उपचार में आयुष्मान कार्ड के अतिरिक्त नकद राशि लिए जाने के संबंध में हाईटेक सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, भिलाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य के नोडल अधिकारी को पत्र लिखा है।

21 गांव के 881 किसान दे रहे आंदोलन की चेतावनी

गैस पाइप लाइन के लिए जबरन जमीन खोद रही कंपनी... मुआवजा भी नहीं

भिलाई। जिले के 21 गांवों के 881 किसानों के खेतों में निजी कंपनी की गैस पाइप लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए किसानों की जमीन चिन्हित की गई है। पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी ने न तो किसानों से अनुमति ली है न कोई मुआवजा दे रही है। सीधे खेतों में खुदाई कर पाइप लाइन बिछा रही है। इससे किसान बेहद नाराज हैं। नाराज किसानों ने 6 मार्च को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके बाद आंदोलन का विस्तार करेंगे।

किसानों का कहना है कि मुताबिक गैस पाइप लाइन के एवज में तीन साल की फसल क्षति के बराबर मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन कंपनी किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। नागपुर और झारसुगुड़ा के बीच निजी कंपनी की गैस पाइप लाइन प्रस्तावित है। यह पाइप लाइन जिले के दुर्ग व धमधा ब्लॉक के 21 गांवों के 881 किसानों के खेतों से होकर गुजरेगी। इनमें टेमरी, रौता, खर्रा, हिर्री, परसदा, नवागांव, पथरिया, डोमा, अहेरी, बागडूमर, बानबरद, ढौर, हींगनडीह, अछोटी, गोढ़ी, ढौर, लहंगा, मलपूरीकला, अंजोरा, ननकट्ठी, बोड़ेगांव, रवेलीडीह आदि गांव शामिल है।

आपत्ति पर दो किमी बाद रोका काम

किसान करीब छह महीने से इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बाद भी कंपनी के कर्मचारियों ने पिछले दिनों रवेली व बोड़ेगांव के आसपास किसानों को बिना कोई सूचना दिए खेतों को रौंदकर व बाउंड्रीवॉल तोड़कर करीब दो किमी पाइप लाइन बिछा दी। हालांकि किसानों के विरोध के बाद कर्मी लौट गए, लेकिन अब किसानों पर दोबारा पाइप लाइन बिछाने दबाव बनाया जा रहा है।

शिकायत का फायदा नहीं, इसलिए आंदोलन

किसानों ने बताया कि लगातार खेतों में पाइप लाइन का विरोध किया जा रहा है। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी की जा चुकी है, लेकिन इस पर कोई भी फैसला अब तक नहीं हो पाया है। इधर कंपनी द्वारा नवागांव में किसी उपयोग के लिए निर्माण की तैयारी की जा रही है। किसान इससे आहत हैं। पिछले दिनों आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अफसरों ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया।

खुदाई के बाद खेती संभव नहीं

पाइप लाइन के लिए खेतों में 10 बाई 4 का गड्ढा खोदा जा रहा है। इसके नीचे पाइप डालकर दबाया जा रहा है। उक्त हिस्से में कम से कम 3 साल फसल संभव नहीं है। ऐसे में 3 साल की फसल क्षति के बराबर मुआवजा का प्रावधान है। किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है।

संपत्तियों को नुकसान का खतरा

कई किसानों ने प्रस्तावित स्थल पर गेहूं आदि फसल लगा रखी है। पाइप लाइन की खुदाई से यह फसल खराब हो रही है। वहीं कई किसानों की खेतों के मेड़, फेंसिंग, ट्यूबवेल, कीमती पेड़, मकान आदि प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए अलग से कोई भी मुआवजा का प्रावधान नहीं किया गया है।

दुर्घटना से नुकसान की आशंका

जिस जगह से होकर पाइप लाइन गुजर रही है, वहां किसान 3 साल फसल नहीं ले पाएंगे। वहीं भविष्य में भी इस जगह का दूसरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा किए जाने से दुर्घटना अथवा जान-माल के नुकसान की आशंका रहेगी। पाइप लाइन में खराबी से भविष्य में भी किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।

निजी कंपनी के उपयोग के लिए शासन-प्रशासन की मदद से किसानों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नियमानुसार किसी भी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसे में किसान एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। अब आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा

भाजपा के शीर्ष नेताओं में बना हुआ है मुंगेली का आकर्षण

वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो वर्ष 1996 से अब तक भाजपा ने मुंगेली जिले के ही नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है।

बिलासपुर। बिलासपुर लोकसभा चुनाव और टिकट वितरण के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के शीर्ष नेताओं और प्रदेश के रणनीतिकारों के बीच मुंगेली जिले का आकर्षण अब भी कायम है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो वर्ष 1996 से अब तक भाजपा ने मुंगेली जिले के ही नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है।

वर्ष 1951 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर वर्ष 1971 तक हुए लोकसभा के चुनाव में बिलासपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लगातार जीत दर्ज की। आपातकाल के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियों में तेजी के साथ बदलाव आया। राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीति में कांग्रेस के कब्जे वाली केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश ऐसे बढ़ा कि सत्ता ही पलट गई। इसका असर बिलासपुर लोकसभा सीट पर दिखाई दिया।

बिलासपुर लोकसभा सीट के आंकड़े

संयुक्त विपक्षी दल की ओर से बिलासपुर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार के रूप में निरंजन प्रसाद केशरवानी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के खिलाफ चल रही लहर का असर यह हुआ कि चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। इसे संयोग ही कहें कि निरंजन प्रसाद केशरवानी मुंगेली जिले से (अविभाजित बिलासपुर जिला, वर्तमान में मुंगेली जिला) सांसद निर्वाचित हुए।

वर्ष 1980, 1984, 1989 व 1991 के चार लोकसभा चुनाव में खेलनराम जांगड़े और रेशमलाल जांगड़े के इर्द-गिर्द कुर्सी आती और जाती रही। वर्ष 1996 से बिलासपुर लोकसभा का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। भाजपा ने जरहागांव के विधायक पुन्नूलाल मोहले को नए चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतारा।

भाजपा का यह प्रयोग सफल रहा। भाजपा के लिए यह सीट अभेद गढ़ के रूप में तब्दील हो गई है। मोहले लगातार चार बार सांसद निर्वाचित हुए। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जशपुर नरेश कुमार दिलीप सिंह जूदेव को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस ने डा रेणु जोगी पर दांव खेला। कांग्रेस का यह प्रयोग असफल रहा। भाजपा के किले को भेद पाने में डा जोगी असफल रहीं।

लखनलाल, अरुण साव और अब तोखन साहू

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने स्व जूदेव की जगह नए चेहरे के रूप में जिला पंचायत सदस्य लखनलाल देवांगन को चुनाव मैदान में उतारा। तब कांग्रेस ने राजनीतिक उलटफेर करने के फेर में करुणा शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारा। करुणा भी भाजपा के किला को भेद नहीं पाई।

वर्ष 2019 में भाजपा ने एक बार फिर नए चेहरे पर दांव खेला और मुंगेली जिले से ताल्लुक रखने वाले अरुण साव को टिकट दिया। भाजपा ने एक बार फिर नए चेहरे पर भरोसा किया और लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसे संयोग ही कह सकते हैं नए चेहरे के रूप में जिन उम्मीदवारों को भाजपा ने मौका दिया है सभी मुंगेली जिले से ही हैं।

अब शनिचरी बाजार के पास मिलेगा पांच रुपये में भोजन

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फेस टू में बिलासपुर का हुआ चयन

बिलासपुर। बृहस्पति बाजार के अलावा अब शनिचरी बाजार क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह अन्य सहायता योजना का विस्तार किया जा रहा है। इस योजना से जरूरतमंद पांच रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह अन्य सहायता योजना का विस्तार शनिचरी बाजार क्षेत्र में किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाने और जल्द फाइल तैयार करने के निर्देश कलेक्टर अवनीश शरण ने विभागीय अफसरों को दिए हैं। सोमवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने मंथन सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में सात मार्च को आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय वीसी से जुड़कर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डीबीटीएल के जरिए योजना की पहली किस्त प्रति हितग्राही एक हजार रुपये चयनित महिलाओं के खाते में अंतरित करेंगे। चुनिंदा हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि विकसित भारत योजना की तर्ज पर महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित होंगे। नगर निगम क्षेत्र के लिए कमिश्नर अमित कुमार और जनपदों के लिए संबंधित एसडीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। बाल विवाह रोकने का संकल्प भी लिया जाएगा। कलेक्टर ने आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की।

पीपीएस साफ्टवेयर में आठ तक

कर्मचारियों की सूची करनी होगी अपडेट

कलेक्टर ने बैठक में लोकसभा चुनाव की चल रही तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा की पीपीएस साफ्टवेयर में आठ मार्च तक कर्मचारियों की सूची अपडेट कर लें और इसकी सत्यापित प्रति एनआइसी में जमा करें। उन्होंने कहा की विधानसभा चुनाव में काम करने कर चुके अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में भी वही जिम्मेदारी सौंप गई है, ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। उन्होंने सेक्टर अधिकारियों को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर समय सीमा में सुधार का कार्य किया जा सके। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बोर्ड बोर्ड परीक्षा के बीच बिजली गुल, मोमबत्ती की रौशनी में पढ़ाई

गरियाबंद। प्रदेश में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रहीं हैं। विधानसभा चुनावों में शिक्षकों की ड्यूटी लगने से स्कूलों में वैसे भी इस बार कम पढ़ाई हुई है। ऐसे में बच्चे जी-जान लगाकर दिन-रात पढ़ाई में जुटे हुए हैं। लेकिन, बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के रास्ते में पावर कंपनी रोड़ा बनकर खड़ी हो गई है। खासतौर पर सुहेला के मामले में। यहां कभी भी, किसी भी वक्त बिजली काट दी जाती है। बढ़ती गर्मी के बीच बच्चे घुटन सहते हुए लालटेन की रौशनी में पढ़ने को मजबूर हैं।

हद तो तब हो गई जब पावर कंपनी ने रविवार को सुबह 10 से 5 बजे तक के लिए बिजली सप्लाई रोक दी। अगले दिन यानी सोमवार को बारहवीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा थी। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए अंगेजी ऐसे ही कठिन विषय है। ऊपर से बिजली कट। ऐसे में बच्चों को एग्जाम की तैयारी करने में काफी परेशानी हुई।

गांव के कई घरों में बच्चे लालटेन जलाकर पढ़ाई करते दिखे। इन दिनों पढ़ाई में मोबाइल बच्चों का बड़ा सहारा है। लेकिन, 7 घटे बिजली न होने से बच्चों को मोबाइल को चार्ज करने का मौका ही नहीं मिला। नतीजतन मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद बच्चों को कई सवालों के जवाब ढूंढने में काफी दिक्कत पेश आई।

इस जिले में 4700 किसानों ने नहीं बेचा धान, 31 मार्च तक 19 करोड़ की करनी है कर्ज वसूली

अंतिम तिथि तक भुगतान नहीं करने पर डिफॉल्टर कर सकते हैं घोषित

बालोद. जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी समाप्त हुए लगभग एक माह बीत गए हैं। वहीं इस साल पंजीकृत किसानों में लगभग 4 हजार 700 किसानों ने धान नहीं बेचा। वहीं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने इस बार जिले के किसानों को कृषि के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज पर कुल 4 अरब 79 करोड़ 8 लाख 57 हजार 82 रुपए का ऋण बांटे थे। जिसके जवाब में 1 लाख 13 हजार 280 किसानों से 4 अरब 59 करोड़ 92 लाख 31 हजार 30 रुपए ऋण वसूली की गई है। जबकि अभी भी सैकड़ों किसानों से 19 करोड़ 16 लाख 26 हजार 52 रुपए की ऋण वसूली करना बाकी है।

जिले में इस खरीफ सीजन बीते साल की तुलना में किसानों ने चुनाव को देखते हुए व चुनाव में कर्ज माफ़ी की उम्मीद के साथ अधिक कर्ज लिया था। लेकिन उम्मीद के उल्टा हुआ। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कर्जमाफ़ी का कोई जादू नहीं चला। वहीं मोदी गारंटी के चलते कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और भाजपा की सरकार बनी। इस वजह से कर्ज माफी भी नहीं हुई।

मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 1 लाख 49 हजार 160 किसान पंजीकृत हैं, जिसमें किसानों ने कुल 4 अरब 79 करोड़ 8 लाख 57 हजार 82 रुपए का ऋण लिया था। वर्तमान में जिन किसानों ने ऋण नहीं जमा किया है, उनसे 31 मार्च तक हर हाल में 19 करोड़ 16 लाख 26 हजार 52 रुपए की ऋण वसूली करनी है। 31 मार्च तक किसानों द्वारा ऋण जमा नहीं कर पाए तो सालाना 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ सकता है। वहीं कर्ज का भुगतान नहीं किया तो किसानों को डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया जाएगा।

सेवा सहकारी समितियां उन किसानों को मौखिक व लिखित सूचना दे रही हैं, जिन्होंने ऋण जमा नहीं किया है। उन्हें कहा जा रहा है कि समय पर कर्ज जमा कर दें। उसके बाद भी किसानों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कई किसान ऐसे हैं, जो बाहर चले गए हैं।

कर्ज जमा नहीं तो आगामी सीजन नहीं मिलेगा कर्ज

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक कर्ज का भुगतान नहीं करने वाले किसान डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं। ऐसे किसानों को आगामी कृषि कार्य के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा। साथ ही कर्ज जमा करने के लिए 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देना पड़ेगा।

ऋण की वसूली की जा रही

नोडल अधिकारी बालोद कुसुम ठाकुर ने कहा कि जिन किसानों ने कृषि कार्य के लिए ऋण लिया है, उन किसानों से ऋण की वसूली की जा रही है। वर्तमान में 19 करोड़ का ऋण और वसूल करना बाकी है, जिसे वसूल किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139